ज्वाला एक्सप्रेस न्यूज

सच्ची खबर सबसे पहले

आर.एन.आई. नं. :- CHHHIN/2021/82386

online- jwalaexpress.com

वर्ष - 05, अंक -44 | दुर्ग (छ.ग.), दिनांक 02 जुलाई से 08 जुलाई (प्रत्येक गुरूवार) | पृष्ठ - 8, मूल्य - 05 रुपए

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बम्हनीडीह के विकास की नई यात्रा का किया शुभारंभ

रायपुर। स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की सबसे सशक्त कड़ी है और नगर पंचायतें केवल प्रशासनिक इकाइयाँ नहीं, बल्कि नागरिकों की आकांक्षाओं को धरातल पर उतारने का प्रभावी माध्यम हैं। नवगठित नगर पंचायत बम्हनीडीह के प्रथम जनप्रतिनिधियों के कंधों पर केवल एक नगर के विकास की नहीं, बल्कि एक नई कार्यसंस्कृति और जनविश्वास की नींव रखने की जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जांजगीर-चांपा जिले के बम्हनीडीह में नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश कुमार डडसेना एवं सभी पार्षदों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जनता ने जिस विश्वास के साथ उन्हें दायित्व सौंपा है, उसका प्रतिफल पारदर्शी प्रशासन, संवेदनशील कार्यशैली और विकास के रूप में दिखाई देना चाहिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बम्हनीडीह के विकास को नई गति देने वाली तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए दहिदा-बम्हनीडीह के बीच हसदेव नदी पर पुल निर्माण, बिजली विभाग का सब डिवीजन कार्यालय तथा सर्वसुविधायुक्त मंगल भवन के निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल आधारभूत संरचनाओं का विस्तार करना नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन को अधिक सुगम, सुरक्षित और सुविधासंपन्न बनाना है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में विकास को नई गति देते हुए हर वर्ग के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाखों परिवारों को पक्के घर, किसानों को उनकी उपज का सम्मानजनक मूल्य, महिलाओं को महतारी वंदन योजना के जरिए आर्थिक संबल तथा युवाओं के लिए रोजगार और अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि विकास का लाभ बिना किसी भेदभाव के समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण केवल बड़े शहरों के विकास से नहीं, बल्कि बम्हनीडीह जैसे उभरते नगरों को सशक्त बनाने से होगा। राज्य सरकार ऐसे सभी नगरीय क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, बेहतर नागरिक सेवाओं और सुनियोजित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बम्हनीडीह नगर पंचायत जनभागीदारी, सुशासन और विकास का एक आदर्श मॉडल बनकर उभरेगी तथा आने वाले वर्षों में क्षेत्र की नई पहचान बनेगी।

रूस का यूक्रेन पर मिसाइल-ड्रोन हमले में 8 लोगों की मौत, 25 घायल

कीव। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया, जिसमें कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई तथा 25 अन्य घायल हो गए।

कीव सैन्य प्रशासन के प्रमुख तिमूर तकाचेंको ने बताया कि हमले में कई आवासीय क्षेत्रों को निशाना बनाया गया और बच्चों सहित बड़ी संख्या में नागरिक हताहत हुए हैं। हमले के बाद शहर के कई इलाकों को खाली कराया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि रूसी सेना ने एक बार फिर जानबूझकर रिहायशी क्षेत्रों को निशाना बनाया है, जिससे भारी तबाही हुई है। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों ने हमले में मृतकों ओर घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई है। यह हमला ऐसे समय हुआ जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कुछ घंटे पहले ही चेतावनी दी थी कि रूस बड़े पैमाने पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। हमले के दौरान कीव में वायु रक्षा प्रणालियां सक्रिय रहीं। आसमान में एयर डिफेंस की ट्रेसर फायरिंग दिखाई दी, जबकि ड्रोन, क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइलों के विस्फोटों की आवाजें पूरे शहर में सुनाई दीं। शहर के विभिन्न हिस्सों में कई स्थानों पर आग लग गई। उधर, पोलैंड ने एहतियात के तौर पर अपने लड़ाकू विमानों को सक्रिय कर दिया। पोलैंड की सेना ने कहा कि यह कदम देश के हवाई क्षेत्र, विशेषकर यूक्रेन से सटे इलाकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। हालांकि, पोलैंड की सीमा में किसी हमले की सूचना नहीं है। रूस का यूक्रेन पर पिछले दो सप्ताह से अधिक समय के अंतराल के बाद यह पहला बड़े पैमाने का मिसाइल और ड्रोन हमला माना जा रहा है।

भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा के लिए संयुक्त रोड मैप तैयार किया : मोदी

जापान/नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत और जापान के बीच आपसी विश्वास को रणनीतिक पूंजी करार देते हुए कहा है कि दोनों देशों के संबंध इसी विश्वास पर टिके हैं और इन्हें और मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों ने आर्थिक सुरक्षा के लिए एक संयुक्त रोड मैप तैयार किया है। मोदी ने भारत की तीन दिन की यात्रा पर आई जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ गुरुवार को यहां भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद कहा कि वैश्विक उथल-पुथल के आज के माहौल में, आपसी विश्वास हमारी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ताकाइची और उनका विश्वास है कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में साझेदारी हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी दृष्टिकोण को साकार करने के लिए, आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के क्षेत्र में हमने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है।

उन्होंने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा।

प्रधानमंत्री ने कहा की रक्षा के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान की पहली शहर विकास परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि साथ ही दोनों देशों ने आर्थिक सुरक्षा के लिए संयुक्त रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने कहा, इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर क्वांटम और उन्नत सामग्रियों जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भी हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा, भारत जापान बायोगैस पहल के माध्यम से हम भारत में एक हजार बायोगैस और कार्बनिक फर्टिलाइजर संयंत्र लगाएंगे।

बिजली गिरने से 48 घंटे में दो लोगों मौत हर पंचायत में तड़ित चालक लगाने की मांग

जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के सन्ना पाठ क्षेत्र में 48 घंटे के भीतर बिजली गिरने से दो लोगों की मौत के बाद बगीचा जिला पंचायत की सामान्य सभा में यह मुद्दा प्रमुखता से उठा, जिसकी जानकारी गुरुवार को मीडिया को दी गयी। जिला सदस्य राकेश गुप्ता ने लगातार हो रही जनहानि पर चिंता व्यक्त करते हुए पूरे पाठ क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत में तत्काल तड़ित चालक उपकरण लगाने की मांग की।

जिला अध्यक्ष गायत्री नागेश की अध्यक्षता में आयोजित सामान्य सभा में विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में विकास कार्यों की समीक्षा की जा रही थी। इसी दौरान गुप्ता ने कहा कि सन्ना पाठ पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहां आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 48 घंटे में दो लोगों की मौत हो चुकी है और कई मचान भी बिजली की चपेट में आकर जल चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रत्येक पंचायत में तड़ित चालक लगाया जाना आवश्यक है।

बीस साल से मूलभूत सुविधाओं का इंतजार सड़क-बिजली के लिए ग्रामीणों की गुहार

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले की ग्राम पंचायत राहुरपुर और उसके आश्रित ग्राम खैरी के ग्रामीण पिछले करीब 20 वर्षों से सड़क, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं लेकिन आज तक उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार बारिश के मौसम में गांव की हालत और भी बदतर हो जाती है। कीचड़ से भरी गलियों और बदहाल सड़कों के कारण लोगों का घर से निकलना मुहाल हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में यदि कोई व्यक्ति अचानक बीमार पड़ जाए तो सबसे बड़ी समस्या उसे अस्पताल तक पहुंचाने की होती है। गांव के अंदर तक एंबुलेंस नहीं पहुंच पाती, क्योंकि सड़कें पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो जाती हैं। ऐसे में मरीज को चारपाई या कंधे के सहारे उठाकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है, जहां से एंबुलेंस मिल पाती है। इससे कई बार मरीज की जान पर भी बन आती है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव की गलियां पूरी तरह कीचड़ और जलभराव से भरी रहती हैं। जगह-जगह पानी जमा होने से जहरीले सांप, बिच्छू और अन्य विषैले जीव-जंतुओं का खतरा बना रहता है। बारिश के दिनों में बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

बिजली व्यवस्था भी ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा रही है। ग्रामीणों के अनुसार कई बार लगातार दो-दो दिनों तक बिजली आपूर्ति बंद रहती है, जिससे लोगों को अंधेरे में रात बितानी पड़ती है। बिजली नहीं रहने से बच्चों की पढ़ाई, घरेलू कामकाज और दैनिक जीवन पूरी तरह प्रभावित होता है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने पिछले दो दशकों में कई बार प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सामने सड़क, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांग रखी है।

वेनेजुएला भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,943 हुई, 10,500 से अधिक घायल

कराकास। वेनेजुएला में आए दो विनाशकारी भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 1943 हो गई है, जबकि 10,571 से अधिक लोग घायल हुए हैं। देश की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने बुधवार को यह जानकारी दी।

रोड्रिगेज ने बताया कि वेनेजुएला और अन्य देशों के विशेषज्ञों ने संयुक्त अभियान चलाकर मलबे से 6,461 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है।

गौरतलब है कि 24 जून को उत्तरी वेनेजुएला में 39 सेकंड के अंतराल पर 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे। पिछले कई दशकों में यह देश में आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में शामिल हैं।

इन दो भूकंपों से राजधानी काराकास, ला गुआइरा और उत्तरी क्षेत्रों में व्यापक तबाही हुई। सैकड़ों इमारतें ढह गईं या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गईं। सड़कें, अस्पताल, स्कूल तथा अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा, जबकि बड़े क्षेत्रों में बिजली और दूरसंचार सेवाएं भी बाधित हुई हैं।

यरुशलम में अमेरिकी दूतावास के स्थायी परिसर के लिए अमेरिका-इजरायल के बीच भूमि आवंटन समझौता

तेल अवीव। इजरायल और अमेरिका ने यरुशलम में अमेरिकी दूतावास के स्थायी परिसर के निर्माण के लिए भूमि आवंटन संबंधी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

इजरायल के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय के अनुसार, विदेश मंत्री गिदोन सार और इजरायल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने यरुशलम के मेयर मोशे लियोन की मौजूदगी में विदेश मंत्रालय में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत यरुशलम में अमेरिकी दूतावास के स्थायी परिसर के निर्माण के लिए भूमि आवंटित की गई है, जिसे इजरायल अपनी शाश्वत राजधानी मानता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह कदम सरकार के उस निर्णय के क्रियान्वयन में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जिसके तहत दूतावास के लिए एलनबी परिसर आवंटित किया गया। यह उस कूटनीतिक प्रक्रिया का भी

महत्वपूर्ण चरण है जिसकी शुरुआत दिसंबर 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यरुशलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता दिए जाने के साथ हुई थी। गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन ने दिसंबर 2017 में यरुशलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता दी थी और 14 मई 2018 को अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से यरुशलम स्थानांतरित कर दिया था। इस फैसले के बाद फ़िलीस्तीनी क्षेत्रों में अशांति फैल गई थी और अरब जगत के कई देशों में विरोध प्रदर्शन हुए थे।

राम मंदिर में चंदा चोरी की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करायें मोदी : कांग्रेस

नयी दिल्ली। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अयोध्या के राम मंदिर में दान राशि की चोरी और गबन के मामले की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराने, जांच का दायरा श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट तथा उससे जुड़े सभी जिम्मेदार व्यक्तियों तक बढ़ाने और मंदिर ट्रस्ट में व्यापक संस्थागत सुधार लागू कर दान व्यवस्था में पूर्ण पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने गुरुवार को मोदी को पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया है कि अयोध्या राम मंदिर में दान राशि की चोरी और गबन के खुलासों से करोड़ों भारतीयों की आस्था पर गहरा आघात है और इससे उनमें आक्रोश और पीड़ा है। करोड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान राम के नाम पर अपनी मेहनत की कमाई मंदिर को दान की, लेकिन उनकी आस्था और

विश्वास के साथ खिलवाड़ किया गया। उन्होंने कहा कि भगवान राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, उनके नाम का पहले राजनीतिक लाभ के लिए और बाद में आर्थिक लाभ के लिए दुरुपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद सार्वजनिक भूमि पर भारत सरकार द्वारा गठित सार्वजनिक ट्रस्ट के माध्यम से हुआ है इसलिए मंदिर के प्रशासन और उसकी कार्यप्रणाली की जवाबदेही पूरी तरह केंद्र सरकार की है। उन्होंने आरोप लगाया कि चोरी को लेकर विभिन्न स्तरों से लगातार चेतावनियां दी जाती रहीं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया गया और जिम्मेदार लोगों ने आंखें मूंदे रखीं, जिससे करोड़ों रुपये की दान राशि की चोरी होती रही।

वेणुगोपाल ने कहा कि प्रारंभिक जांच से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि यह चोरी का मामला कुछ कर्मचारियों तक ही सीमित मामला नहीं है, बल्कि यह पूरा मामला एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा है। नकदी और आभूषणों की हेराफेरी, सात से आठ महीने की सीसीटीवी फुटेज का गायब होना, पूर्व मुख्य लेखा अधिकारी की शिकायतों की अनदेखी करना तथा भारतीय स्टेट बैंक की ओर से दान की गणना में अनियमितताओं को लेकर जतायी गयी चिंताओं पर भी ध्यान नहीं दिया गया।

मजदूर खदान में पत्थर तोड़ने और खुदाई का काम कर रहे थे

बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा : पत्थर की खदान में 40 फीट ऊंची चट्टान गिरी, 7 मजदूरों की गई जान-कई घायल

बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। बेंगलुरु साउथ तालुक के मादापट्टना इलाके स्थित एक पत्थर की खदान में अचानक विशालकाय चट्टान ढहने से बिहार के 7 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य मजदूर घायल हो गए।

पुलिस के अनुसार, हादसा उस समय हुआ जब मजदूर खदान में पत्थर तोड़ने और खुदाई का काम कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, साइट पर करीब 18 मजदूर मौजूद थे। इसी दौरान लगभग 40 फीट की

ऊंचाई से एक भारी-भरकम चट्टान अचानक मजदूरों पर आ गिरी, जिससे अफरा-तफरी मच गई। मृतक सभी दिहाड़ी मजदूर थे और स्टोन क्रशर साइट पर काम करते थे।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंच गए। मलबा हटाने का अभियान तुरंत शुरू किया गया और घायलों को इलाज के लिए नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रशासन अभी घायलों की संख्या और मलबे में अन्य मजदूरों के फंसे होने की आशंका की जांच कर रहा है। हादसे के बाद प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को सील कर दिया है। राहत दल यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि मलबे के नीचे कोई अन्य व्यक्ति न फंसा हो। पुलिस ने पुष्टि की है कि हादसे में जान गंवाने वाले सभी सात मजदूर बिहार के रहने वाले थे। उनके परिजनों को घटना की सूचना दी जा रही है। वहीं, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि हादसा किन कारणों से हुआ और क्या खदान में सुरक्षा मानकों की अनदेखी या किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई थी।

दिल्ली में बड़ा आतंकी मॉड्यूल ध्वस्त आईएसआई समर्थित 4 आतंकी गिरफ्तार

पाकिस्तान के इशारे पर दहशत फैलाने की थी साजिश

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े अंतरराज्यीय ऑपरेशन में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े आतंकी और हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान दिल्ली और पंजाब से चार संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच के मुताबिक, ये सभी पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के इशारे पर दिल्ली-एनसीआर में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तुर्की निर्मित जिगाना पिस्टल समेत दो विदेशी सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल, नौ कारतूस और पांच मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

स्पेशल सेल के डीसीपी प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि एसीपी विवेक कुमार त्यागी, इंस्पेक्टर सतीश राणा और इंस्पेक्टर अशोक की टीम को तकनीकी और खुफिया सूचना मिली थी कि पाकिस्तान में बैठा आईएसआई हैंडलर शाहजाद भट्टी अपने नेटवर्क के जरिए दिल्ली-एनसीआर में बड़ी आतंकी घटना की साजिश रच रहा है। इसके लिए पंजाब के कुछ युवाओं को अपने जाल में फंसाया गया था। प्रारंभिक जांच के बाद स्पेशल सेल ने भारतीय न्याय संहिता और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

इसके बाद दिल्ली और पंजाब में कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई। सबसे पहले पंजाब के अमृतसर के मजीठा रोड इलाके से शुभदीप सिंह उर्फ विशाल को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल, पांच कारतूस और दो मोबाइल फोन बरामद हुए।

एक्शन मोड में कलेक्टर: 'स्कूल जतन' से लेकर 'आजीविका' तक

हर योजना की जमीनी स्तर पर होगी मॉनिटरिंग, जनहित के कार्यों को मिलेगी प्राथमिकता

सुकमा। जिला प्रशासन सुकमा क्षेत्र के समग्र विकास, बुनियादी ढांचे की मजबूती और जन कल्याणकारी योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में कलेक्टर अमित कुमार ने जिला पंचायत सभाकक्ष में मंगलवार को समय-सीमा की एक उच्च स्तरीय बैठक लेकर विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं विभागीय कार्यों की सघन समीक्षा की। प्रशासन का मुख्य फोकस इस समय मैदानी स्तर पर योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक पहुंचाना है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जनहित के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में शिक्षा के स्तर को सुधारने और नौनिहालों के भविष्य को सुरक्षित करने पर विशेष बल दिया गया। कलेक्टर ने स्कूलों में नव प्रवेशी एवं कक्षा पहली के बच्चों के जाति, निवास और आमदनी प्रमाणपत्र बनाने की प्रक्रिया को तत्काल तेज करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत पोर्टाकेबिन, कस्तूरबा गांधी और पीएम विद्यालयों में पठन-पाठन की बेहतर व्यवस्था

सुनिश्चित करने को कहा गया है। शाला त्यागी बच्चों के डेटा में गड़बड़ी पाए जाने पर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं, आगामी सत्र को देखते हुए 1 तारीख से साइंस पार्क को पुनः खोलने और श्वैगलेस डेश् के तहत श्मायद नोनीश् सिविक सेंस मॉड्यूल को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए गए। ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए जिला प्रशासन ने बेहद ठोस कदम उठाए हैं। कलेक्टर ने जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त दवाओं की उपलब्धता और मेडिकल स्टाफ की मुख्यालय में नियमित उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। इसके अलावा, आयुष्मान कार्ड की कार्यप्रगति, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती और निर्माणाधीन आंगनवाड़ी नत स्कूल भवनों को जल्द पूरा करने की समीक्षा की गई। हाई रिस्क प्रेग्नेंसी, संस्थागत प्रसव और कुपोषण नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग को आपसी समन्वय (स्कूल-आंगनवाड़ी लिंकेज) के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सुकमा को कुपोषण मुक्त बनाया जा सके। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के माध्यम से स्व-सहायता समूहों को आगामी त्योहारों के मद्देनजर सामग्री उत्पादन और विक्रय के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसके साथ ही आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस और पंचायत कैफे की कार्यप्रगति की भी समीक्षा की गई। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कोंटा में चल रहे विकास कार्यों, जल संसाधन विभाग के प्रोजेक्ट्स, सामुदायिक शौचालयों के निर्माण और साप्ताहिक जियो-टैगिंग के कार्य में तेजी लाने को कहा गया है। किसानों की सहूलियत के लिए धान उठाव, खाद-बीज भंडारण और पीएम स्वनिधि योजना की भी विस्तृत समीक्षा की गई। प्रशासन पारदर्शिता और त्वरित कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए राशन कार्ड के ई-केवाईसी का कार्य 15 जुलाई तक पूर्ण करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही बैंक खातों के सत्यापन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी जन-हितैषी योजनाओं के लाभार्थियों के डेटा का मिलान किया जा रहा है। छात्रों के कल्याण को देखते हुए हॉस्टलों में नियमित साफ-सफाई और मच्छरों से बचाव के लिए अनिवार्य रूप से मच्छरदानी वितरण के निर्देश दिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा 5 जुलाई को उप अंकेक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आगामी 05 जुलाई 2026 को जगदलपुर शहर के तीन परीक्षा केंद्रों में सहकारिता विभाग के अन्तर्गत उप अंकेक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया है। जिसके तहत शासकीय काकतीय पीजी कॉलेज धरमपुरा जगदलपुर, झाड़ा सिरहा शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज धरमपुरा जगदलपुर और शासकिय दंतेश्वरी पीजी कॉलेज शांति नगर जगदलपुर में उक्त परीक्षा 05 जुलाई को प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय से ठीक ढाई घंटे पहले अपने-अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना अनिवार्य होगा, जहां मुख्य द्वार पर ही मेटल डिटेक्टर के माध्यम से सभी की सघन जांच की जाएगी। इसके बाद वहां तैनात वीक्षकों द्वारा परीक्षार्थियों के मूल प्रवेश पत्र और उनके साथ लाए गए किसी भी एक वैध पहचान पत्र के सत्यापन की कार्रवाई की जाएगी। नियमों के तहत परीक्षार्थियों को इंटरनेट से निकाला हुआ साफ-सुथरा मूल प्रवेश पत्र लाना जरूरी है और यदि किसी छात्र के प्रवेश पत्र में फोटो स्पष्ट नहीं है, तो उन्हें अपने साथ वर्तमान समय की दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लाने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा हॉल के भीतर अनुशासन बनाए रखने के लिए विशेष ड्रेस कोड और प्रतिबंध तय किए गए हैं। परीक्षार्थियों को हल्के रंग की हाफ टी-शर्ट और हल्के कपड़े पहनकर आना होगा, साथ ही पैरों में केवल चप्पल पहनने की अनुमति होगी क्योंकि परीक्षा केंद्र के भीतर जूता-मोजा पहनकर जाना पूरी तरह से वर्जित किया गया है। इसके अलावा कान में किसी भी प्रकार के आभूषण, जैसे बाली या झुमका आदि पहनने पर सख्त रोक रहेगी. परीक्षा कक्ष में घड़ी, पर्स, मोबाइल, बेल्ट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, संचार के साधन, स्कार्फ, टोपी और चश्मा जैसी सामग्रियां ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए नोडल अधिकारी के रूप में डिप्टी कलेक्टर श्री मनीष कुमार वर्मा (मो. 9406349496) को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं डॉ. अनिल श्रीवास्तव को समन्वयक और डॉ. अजय सिंह ठाकुर को सहायक समन्वयक नियुक्त किया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री ने महारानी अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, 300 बिस्तर विस्तार और नई सुविधाओं को सुनिश्चित करने दिए निर्देश

जगदलपुर। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बस्तर अंचल के महारानी अस्पताल का औचक निरीक्षण कर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को अस्पताल की गौरवशाली पहचान के अनुरूप मानवीय संवेदनाओं के साथ मरीजों को बेहतर उपचार एवं सेवा प्रदान करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल को आम लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप अधिक सुविधाजनक और बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने अस्पताल की वर्तमान 200 बिस्तर क्षमता को बढ़ाकर 300 शैयायुक्त करने के निर्देश देते हुए नए सेटअप तथा अस्पताल भवन उन्नयन का प्रस्ताव विभाग को भेजने कहा। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अस्पताल में डायलिसिस सेंटर एवं कैंसर यूनिट के निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अस्पताल परिसर की अंदरूनी सड़कों की मरम्मत भी शीघ्र करवाने कहा। उन्होंने अस्पताल के आपातकालीन चिकित्सा कक्ष, ओपीडी, ईसीजी यूनिट तथा ब्लड बैंक का निरीक्षण किया और उपचार के लिए आए मरीजों तथा उनके परिजनों से आत्मीयता से चर्चा कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मंत्री ने अटल आरोग्य लैब का भी निरीक्षण करते हुए यहां उपलब्ध जांच सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की तथा आवश्यक उपकरणों की शीघ्र स्थापना कर सभी 134 प्रकार की जांच सुविधाएं जल्द सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टर्स डे के अवसर पर महारानी अस्पताल में केक काटकर चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने सभी चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों से समर्पण और सेवा भाव के साथ चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने का आह्वान किया।

आतंक के साए से निकली नई सुबह: 21 साल बाद पीडिया में फिर गूंजी स्कूल की घंटी, 539 बच्चों को मिला शिक्षा का अधिकार

बीजापुर। कभी माओवादी आतंक और हिंसा के कारण वीरान पड़े पीडिया क्षेत्र में अब बच्चों की किलकारियां और स्कूल की घंटियां सुनाई देने लगी हैं। 21 वर्षों तक बंद रहने के बाद बीजापुर जिले के पीडिया क्षेत्र के 11 स्कूलों का पुनः संचालन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल और कलेक्टर विश्वदीप के मार्गदर्शन में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रयासों से अब 11 गांवों के 539 बच्चों को अपने ही गांव में शिक्षा का अधिकार मिल रहा है। यह केवल स्कूलों के पुनः खुलने की कहानी नहीं, बल्कि भय से विश्वास और अंधकार से ज्ञान की ओर बढ़ते बस्तर की नई पहचान है। पीडिया में आयोजित प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने 11 गांवों के शिक्षादूतों को रजिस्टर एवं शिक्षण सामग्री प्रदान की तथा बच्चों को स्कूल बैग, कॉपी, पेन और स्लेट वितरित कर उनका विद्यालय में प्रवेश कराया।कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष सोनू पोटाम, जनपद उपाध्यक्ष दिनेश पुजारी, सरपंच सन्नू अवलम सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अतिथियों

ने बच्चों का तिलक लगाकर, गुलाल लगाते हुए और लड्डू खिलाकर उनका स्वागत किया तथा उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि अब पीडिया क्षेत्र विकास के नए दौर में प्रवेश कर रहा है और शिक्षा उसकी सबसे मजबूत नींव है। उन्होंने कहा कि सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें। उन्होंने आश्वस्त किया कि विद्यालयों में भवन, पेयजल, बिजली सहित सभी आवश्यक सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराई जाएंगी।जनपद अध्यक्ष सोनू पोटाम ने कहा कि पीडिया में बच्चों के कंधों पर स्कूल बैग देखना पूरे क्षेत्र के लिए गर्व और खुशी का क्षण है। यह बदलाव विकास की नई दिशा तय करेगा। जनपद उपाध्यक्ष दिनेश पुजारी ने कहा कि वर्षों बाद गांवों में स्कूलों का फिर से खुलना ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार और जिला प्रशासन बधाई के पात्र हैं। सरपंच सन्नू अवलम ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ग्रामीण शिक्षा के विकास में हरसंभव सहयोग करेंगे।

21 साल बाद इन 11 गांवों में लौटी शिक्षा

सलवा जुडूम के दौरान माओवादी हिंसा के कारण पीडिया क्षेत्र के कई स्कूल बंद हो गए थे और उनके भवन भी ध्वस्त कर दिए गए थे। अब जिन गांवों में विद्यालयों का पुनः संचालन शुरू हुआ है, उनमें पीडिया, पेदापाल, छोटेगोटोडी, कुएम, मदपाल, अंडरी, इडेनार, डोंडीतुमनार, मिरगानघोटूल, गमपुर और तमोड़ी शामिल हैं। इन गांवों के बच्चों को अब शिक्षा के लिए दूरस्थ क्षेत्रों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। f

जला शिक्षा अधिकारी राजेश पांडे ने बताया कि कलेक्टर विश्वदीप एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की पहल पर जिले में बंद स्कूलों को मूल गांवों में पुनः संचालित करने का अभियान लगातार जारी है। इस वर्ष अब तक 20 प्राथमिक एवं 17 उच्च प्राथमिक, कुल 37 स्कूलों का संचालन दोबारा शुरू किया जा चुका है। इन विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है।

मड़कम देवा ने झींगा पालन को बनाया आत्मनिर्भरता का जरिया

सुकमा। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सहायक व्यवसायों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में

सुकमा जिले में नीली क्रांति ग्रामीण विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता का एक नया और सशक्त आधार बनकर उभरी है। कम लागत, कम समय में बेहतर मुनाफे और बाजार में बढ़ती मांग के कारण मत्स्य व मीठे पानी में झींगा पालन की लोकप्रियता ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के खेती को सिर्फ धान तक सीमित न रखकर उद्यानिकी, दुग्ध और मत्स्य पालन जैसे आयवर्धक क्षेत्रों से जुड़ने के आह्वान का असर अब जमीन पर साफ दिखने लगा है। शासन की कल्याणकारी योजनाएं आज ग्रामीण युवाओं और पारंपरिक किसानों के लिए संबल साबित हो रही हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण सुकमा जिले के दुब्बाटोटा निवासी मड़कम देवा हैं, जिन्होंने शासकीय योजनाओं का लाभ उठाकर झींगा और मछली पालन को अपना मुख्य व्यवसाय बनाया। मत्स्य पालन विभाग द्वारा उन्हें तालाब निर्माण के लिए 7.20 लाख रूपये का लोन स्वीकृत किया गया, जिसमें 4.20 लाख रूपये का भारी अनुदान शामिल था। इसके साथ ही, 24 घंटे पानी की सुचारू सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्रेड़ा विभाग द्वारा उन्हें सब्सिडी पर सोलर पंप की अनमोल सुविधा भी दी गई, जिसने उनकी राह बेहद आसान कर दी। मड़कम देवा ने न सिर्फ वित्तीय सहायता का लाभ लिया, बल्कि कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग से समय-समय पर आधुनिक मत्स्य पालन का तकनीकी प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। इसी वैज्ञानिक पद्धति और कड़ी मेहनत का नतीजा है कि इस वर्ष अकेले जून माह में ही उन्होंने लगभग 2.50 क्विंटल झींगा और 15 क्विंटल मछली की बंपर बिक्री की। इस उत्पादन से उन्हें करीब 5 लाख रूपये की शानदार आय अर्जित हुई है। झींगा पालन के क्षेत्र में सुकमा का नाम रोशन करने के लिए विश्व पशु चिकित्सा दिवस के अवसर पर रायपुर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में कृषि मंत्री रामविचार नेताम के हाथों मड़कम देवा को सम्मानित भी किया जा चुका है। दूर दूर से लोग दुब्बा टोटा मछली और झींगा खरीदने के लिए आते हैं। कलेक्टर अमित कुमार ने बताया कि सुकमा जिला प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और यहाँ मीठे पानी के झींगा पालन की अपार संभावनाएँ हैं। मड़कम देवा जैसे प्रगतिशील किसान आज हमारे ग्रामीण युवाओं के लिए रोल मॉडल बन रहे हैं।

बिहान की दीदी के परिवार को मिला आर्थिक सहारा

सुकमा। जिला प्रशासन के कुशल मार्गदर्शन में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सुदूर और अंतिम छोर पर बसे ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसी कड़ी में सुकमा जिले के सुदूर विकासखंड कोंटा के ग्राम आरलमपल्ली में एक पीड़ित

परिवार को असमय दुख की घड़ी में त्वरित आर्थिक संबल प्राप्त हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुकमा जिले के आखिरी छोर पर स्थित विकासखंड कोंटा के ग्राम आरलमपल्ली की ÷दुर्गा स्व-सहायता समूह÷ से जुड़ी बिहान की दीदी दुधी सन्नी का बीते 08 अप्रैल 2026 को आकस्मिक निधन हो गया था। इस असमय वज्रपात से पीड़ित परिवार गहरे संकट में डूब गया था। इस संवेदनशील मामले में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुकुंद ठाकुर के कुशल मार्गदर्शन व त्वरित निर्देशानुसार बिहान योजना की पीआरपी एवं एफएलसीआरपी ने अद्वितीय तत्परता दिखाई। संबंधित टीम द्वारा बिना किसी विलंब के मृतिका का त्वरित बीमा प्रकरण तैयार किया गया और इसे भारतीय स्टेट बैंक की दोरनापाल शाखा में प्रेषित किया गया। एसबीआई शाखा प्रबंधक ने भी मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए सभी आवश्यक दस्तावेजीकरण की प्रक्रियाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा किया और क्लेम को तत्काल उच्च कार्यालय को अग्रसारित कर दिया। प्रशासनिक और बैंक की संयुक्त मुस्तैदी का ही नतीजा रहा कि मृतिका के पति व नामिनी दुधी सोमा के बैंक खाते में मात्र दो महीने के भीतर, यानी 27 मई 2026 को 2,00,000 (दो लाख रुपये) की दावा राशि सफलतापूर्वक प्राप्त हो गई। इस राशि का आधिकारिक भुगतान नगर पंचायत अध्यक्ष राधा नायक के कर-कमलों द्वारा चेक के माध्यम से हितग्राही को किया गया। वित्तीय सहायता राशि सही समय पर प्राप्त होने से पीड़ित परिवार को इस कठिन समय में बड़ा संबल मिला है। इस त्वरित और लोक-कल्याणकारी कार्य को गति देने में भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक आनंद सिंह, बिहान की पीआरपी रूकमणी कर्मा एवं एफएलसीआरपी कुमारी शालिनी ओडला की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही। इनके संयुक्त एवं समर्पित प्रयासों से ही सुदूर वनांचल में रह रहे प्रभावित परिवार को अत्यंत तीव्र गति से आर्थिक सहायता सुलभ हो सकी है।

एनएमडीसी डीएवी आईटीआई भांसी के स्टाफ व छात्रों ने किया रक्तदान, जरूरतमंदों की मदद का दिया संदेश

बचेली। सामाजिक सरोकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निभाते हुए एनएमडीसी डीएवी आईटीआई, भांसी के स्टाफ एवं प्रशिक्षुओं ने बुधवार एनएमडीसी अपोलो अस्पताल, बचेली में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में उत्साहपूर्वक भाग लेकर रक्तदान किया। शिविर में कुल 25 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। रक्तदान शिविर का संचालन एनएमडीसी अपोलो अस्पताल, बचेली की चिकित्सकीय टीम द्वारा किया गया। रक्तदान से पूर्व सभी रक्तदाताओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा सुरक्षित तरीके से रक्त संग्रह किया गया। शिविर में रक्तदान करने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक स्वास्थ्य

संबंधी परामर्श भी प्रदान किए गए। संस्था प्रबंधन ने रक्तदान करने वाले सभी स्टाफ, प्रशिक्षुओं एवं एनएमडीसी अपोलो अस्पताल की चिकित्सकीय टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में भी ऐसे जनहित के कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर एनएमडीसी बचेली परियोजना के उप-महाप्रबंधक (मा.सं.) सीएसआर जोसी थॉमस एवं संस्था के प्राचार्य कमलेश साहू भी उपस्थित रहे।

सखी वन स्टॉप सेंटर के कार्यालय सहायक पद की अंतिम वरीयता सूची जारी

बीजापुर। महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बीजापुर द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर अंतर्गत रिक्त कार्यालय सहायक के एक पद पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर पात्र अभ्यर्थियों की अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी गई है।जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने बताया कि 09 जनवरी 2026 के माध्यम से उक्त पद के लिए योग्य अभ्यर्थियों से 09 जनवरी 2026 से 19 जनवरी 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त आवेदनों की जांच, पात्रता परीक्षण एवं चयन संबंधी समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत पात्र अभ्यर्थियों की अंतिम वरीयता सूची तैयार की गई है।विभाग द्वारा जारी अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। संबंधित अभ्यर्थी विभागीय सूचना पटल एवं कार्यालय में प्रदर्शित सूची का अवलोकन कर सकते हैं।

25 हजार रुपये के ऋण से बदली पूनम की तकदीर, बकरी पालन और सब्जी उत्पादन से बनीं आत्मनिर्भरता की मिसाल

रायपुर। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। इसी कड़ी में बलरामपुर जिले के ग्राम लुरघुट्टा की श्रीमती पूनम कुशवाहा ने मात्र 25 हजार रुपये के छोटे से ऋण को आजीविका के बड़े अवसर में बदलकर आत्मनिर्भरता की प्रेरक मिसाल प्रस्तुत की है।जिला प्रशासन के मार्गदर्शन से महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों का ही परिणाम है कि श्रीमती पूनम कुशवाहा आज अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ-साथ अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं।एक समय ऐसा था जब परिवार की आजीविका केवल उनके पति की सीमित आय पर निर्भर थी, जिससे घरेलू जरूरतों को पूरा करना चुनौतीपूर्ण था। परिवार की आय

बढ़ाने की इच्छा तो थी, लेकिन संसाधनों और पूंजी की कमी रास्ते में बाधा बनी हुई थी। इसी दौरान पूनम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत पार्वती महिला स्व-सहायता समूह से जुड़ीं। समूह से जुड़ने के बाद उन्हें नियमित बचत, प्रशिक्षण और बैंक लिंकेज जैसी सुविधाएं मिलीं तथा 25 हजार रुपये का ऋण प्राप्त हुआ।श्रीमती पूनम ने इस राशि का उपयोग उन्नत नस्ल की बकरियां खरीदने में किया और वैज्ञानिक पद्धति से बकरी पालन शुरू किया। बकरियों से प्राप्त जैविक खाद का उपयोग करते हुए उन्होंने अपनी बाड़ी में टमाटर, मिर्च, बैंगन सहित विभिन्न मौसमी सब्जियों का उत्पादन भी प्रारंभ किया। आज स्थानीय बाजार में सब्जियों की बिक्री और बकरियों के विक्रय से उन्हें नियमित आय प्राप्त हो रही है।इस अतिरिक्त आय से बच्चों की शिक्षा, परिवार की आवश्यकताओं और भविष्य की जरूरतों को पूरा करना आसान हुआ है। साथ ही वे स्व-सहायता समूह से लिए गए ऋण का समय पर भुगतान भी कर रही हैं।श्रीमती पूनम कहती हैं कि स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्हें आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की नई दिशा मिली है। उनका मानना है कि छोटा सा आर्थिक सहयोग भी यदि सही दिशा में उपयोग किया जाए, तो वह जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है।

दिवंगत शासकीय कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति, कलेक्टर ने सौंपे नियुक्ति आदेश

बीजापुर। शासकीय सेवकों के सेवाकाल के दौरान दिवंगत हुए शासकीय कर्मचारियों के आश्रित परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों के त्वरित एवं संवेदनशील निराकरण के तहत आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा दो आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई।

जिला बीजापुर के आदिवासी बहुल क्षेत्र अंतर्गत आदिवासी विकास विभाग में संचालित कन्या आश्रम इलमिडी, विकासखंड उसूर में कार्यरत दिवंगत चिन्नाबाई चापा के निधन के पश्चात उनके पुत्र रमेश चापा, ग्राम इलमिडी, पोस्ट इलमिडी, जिला बीजापुर को बालक आश्रम पुसबाका में भृत्य के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई। इसी प्रकार बालक छात्रावास नैमेड, विकासखंड बीजापुर में कार्यरत दिवंगत पलसूराम खलखो के निधन के पश्चात उनकी पुत्री कुमारी मोनिका खलखो, ग्राम दुगोली, पोस्ट नैमेड, जिला बीजापुर को कन्या छात्रावास उसूर में भृत्य के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई। कलेक्टर जिला बीजापुर विश्वदीप ने दोनों नियुक्त कर्मचारियों को नियमित भृत्य पद के नियुक्ति आदेश सौंपते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दीं। इस अवसर पर कलेक्टर विश्वदीप ने रमेश चापा एवं कुमारी मोनिका खलखो से आत्मीय चर्चा करते हुए कहा कि वे पूरी लगन, निष्ठा एवं जिम्मेदारी के साथ अपने शासकीय दायित्वों का निर्वहन करें तथा जनसेवा के प्रति समर्पित भाव से कार्य करते हुए विभाग की गरिमा को बनाए रखें। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों कर्मचारी अपने कर्तव्यों का ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक निर्वहन कर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से आमजन तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।इस अवसर पर सहायक आयुक्त देवेन्द्र सिंह उपस्थित थे।

बम्हनी उपार्जन केंद्र में 77 लाख से अधिक का धान घोटाला, 2386क्विंटल धान गायब

प्रबंधक से लेकर निगरानी तंत्र तक जिम्मेदारी पर उठे गंभीर सवाल

कवर्धा। कबीरधाम जिले के उपार्जन केंद्र बम्हनी (समनापुर) में सामने आए 77 लाख रुपये से अधिक के धान घोटाले ने समर्थन मूल्य खरीदी व्यवस्था की साख पर गहरा दाग लगा दिया है। सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज धान और वास्तविक भंडारण के बीच भारी अंतर ने न केवल खरीदी व्यवस्था की पोल खोल दी है, बल्कि यह भी संकेत दिया है कि बिना अंदरूनी संरक्षण के इतनी बड़ी गड़बड़ी संभव नहीं थी। मामला अब केवल धान की कमी तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि पूरे निगरानी तंत्र की जवाबदेही तय करने तक पहुंच गया है। जानकारी के अनुसार उपार्जन केंद्र बम्हनी (समनापुर) में 15 नवंबर 2025 से 6 फरवरी 2026 के बीच कुल 55,220.40 क्विंटल धान की खरीदी की गई थी। लेकिन 12 जून 2026 को संयुक्त जांच दल द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ऑनलाइन स्टॉक और वास्तविक भंडारण के बीच 2386.52 क्विंटल धान की कमी पाई गई। गायब धान की कीमत 73,98,212 रुपये आंकी गई। इतना ही नहीं, जांच में 8554 नग उपयोग विहीन बारदानों की कमी भी सामने आई, जिसकी कीमत 3,27,793 रुपये बताई गई। इस प्रकार कुल 77,26,005 रुपये की आर्थिक क्षति होना

पाया गया। मामले में रैंगाखार थाना में समिति प्रबंधक अनिल चंद्राकर, उपार्जन केंद्र प्रभारी मतु लाल झरिया और कंप्यूटर ऑपरेटर छन्नू साहू के खिलाफ अपराध दर्ज किया जा चुका है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मामला दर्ज होने के बाद भी तीनों आरोपी अब तक पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं और फरार बताए जा रहे हैं। इससे पुलिस कार्रवाई की गंभीरता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इतने बड़े आर्थिक अपराध के आरोपी अब तक गिरफ्त से बाहर होना अपने आप में कई संकेत दे रहा है। इस पूरे मामले का सबसे गंभीर पहलू यह है कि प्रति सप्ताह नोडल अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाता था। नियमों के अनुसार उपार्जन केंद्रों में नियमित सत्यापन अनिवार्य होता है। इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। साथ ही एक निगरानी समिति भी गठित रहती है, जिसका अध्यक्ष और सदस्य पूरे स्टॉक, बारदाना और भंडारण व्यवस्था की निगरानी के लिए जिम्मेदार होते हैं। यदि हर सप्ताह निरीक्षण हुआ, तो 2386 क्विंटल धान और हजारों बारदानों की कमी आखिर किसी की नजर में क्यों नहीं आई। यह स्थिति पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर सीधा प्रहार करती है। साफतौर पर दो ही संभावनाएं दिखाई देती हैं–या तो भौतिक सत्यापन केवल कागजों में पूरा किया गया, या जिम्मेदार अधिकारियों ने जानबूझकर आंखें मूंद लीं। दोनों ही स्थितियां बेहद गंभीर और चिंताजनक हैं। हजारों क्विंटल धान का गायब होना किसी छोटी तकनीकी त्रुटि का परिणाम नहीं माना जा सकता। इतने बड़े स्तर पर धान की कमी एक दिन में नहीं होती। यह लंबे समय से चल रही सुनियोजित अनियमितता का संकेत है। यदि धान धीरे-धीरे बाहर किया गया, तो परिवहन, भंडारण, रजिस्टर प्रविष्टि और ऑनलाइन रिकॉर्ड तक कई स्तरों पर मिलीभगत की आशंका स्वाभाविक रूप से सामने आती है। ऐसे में केवल समिति प्रबंधक, केंद्र प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर पर मामला दर्ज कर देना पर्याप्त कार्रवाई नहीं माना जा सकता। अब जिम्मेदारी तय करने के लिए यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि साप्ताहिक भौतिक सत्यापन करने वाले नोडल अधिकारी कौन थे, निगरानी समिति के अध्यक्ष और सदस्य कौन थे, सत्यापन रिपोर्ट में स्टॉक हमेशा सही कैसे दर्शाया गया और उच्च अधिकारियों तक वास्तविक स्थिति क्यों नहीं पहुंची। यदि जांच केवल निचले स्तर के कर्मचारियों तक सीमित रही, तो इसे अधूरी कार्रवाई माना जाएगा। इतने बड़े घोटाले में प्रशासनिक जवाबदेही तय करना अनिवार्य है।

नोडल अधिकारी, निगरानी समिति, संबंधित सहकारी विभाग और खरीदी व्यवस्था से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच समय की मांग बन चुकी है। बम्हनी उपार्जन केंद्र का यह मामला स्पष्ट चेतावनी है कि जब निगरानी तंत्र ही निष्क्रिय या संदिग्ध हो जाए, तब सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार को खुली छूट मिल जाती है। अब जनता यह जानना चाहती है कि 77 लाख रुपये से अधिक की क्षति का असली जिम्मेदार कौन है–केवल तीन फरार आरोपी या पूरा वह तंत्र जिसने समय रहते इस घोटाले को रोकने के बजाय उसे पनपने दिया। जब तक हर जिम्मेदार व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक यह मामला प्रशासनिक लापरवाही और जवाबदेही पर बड़ा सवाल बना रहेगा।

दल्लीराजहरा में सतगुरु कबीर साहेब की जयंती मनाई गई

दल्लीराजहरा। सतगुरु कबीर साहेब की जयंती दल्लीराजहरा में श्रद्धा, सेवा और रोशनी के संगम के साथ मनाई गई। मानिकपुरी पनिका समाज ने दिनभर चले कार्यक्रमों में नगरवासियों को कबीर के दोहों से जोड़ने का काम किया। कार्यक्रम की शुरुआत जैन भवन चौक से हुई। गुरुदेव कबीर साहेब की तस्वीर की पूजा-अर्चना के बाद मानिकपुरी पनिका समाज ने नगरवासियों के लिए प्रसादी के रूप में पोहा, चना और मीठा शरबत वितरित किया। दोपहर तक चौक में भीड़ लगी रही और हजारों लोगों ने कबीर के सेवा भाव को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। मानिकपुरी पनिका समाज के नगर अध्यक्ष रामदास मानिकपुरी ने कहा, कबीर साहेब सिर्फ संत नहीं, एक बड़े समाज सुधारक थे। उनका दोहा - बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय - हमें सिखाता है कि मन साफरखो। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोय - यह समानता का संदेश है। कबीर खड़े बाजार में, सबकी मागे खैर - यह पूरी दुनिया के लिए मंगल कामना है। शाम होते ही कबीर मंदिर का माहौल भक्तिमय हो गया। समाज के सैकड़ों महिला-पुरुषों की उपस्थिति में 1001 दीपों के साथ भव्य महा आरती की गई। दीपों की लौ में पूरा मंदिर जगमगा उठा और साहेब बंदगी साहेब के जयकारे से आकाश गूंज उठा। कबीर साहेब की इस जयंती ने एक बार फिर साबित किया कि कबीर कोई संप्रदाय नहीं, बल्कि जीवन जीने की सोच हैं। और दल्ली राजहरा का भाईचारा उसी सोच का सबसे बड़ा उदाहरण है।

सरस्वती साइकिल योजना के तहत छात्राओं को मिली साइकिल

धमतरी। ग्राम मुजगहन स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत छात्राओं को साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री ओमेश यादव रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत सदस्य धनेश्वरी साहू ने की।

इस अवसर पर सरपंच होमेश्वर साहू, प्राचार्य मोनिका गोस्वामी, विद्यालय परिवार, अभिभावक एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ओमेश यादव ने अपने उद्बोधन में कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन

कर रही है। सरस्वती साइकिल योजना बेटियों के सपनों को नई उड़ान देने वाली महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने छात्राओं से मन लगाकर अध्ययन करने, अनुशासन का पालन करने तथा अपने परिवार, विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन करने का आह्वान किया। जिला पंचायत सदस्य धनेश्वरी साहू ने छात्राओं को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि शिक्षित बेटियाँ समाज और राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति हैं। प्राचार्य मोनिका गोस्वामी ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए छात्राओं से इस योजना का लाभ उठाकर नियमित अध्ययन करने और अपने उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करने का आग्रह किया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने छात्राओं को साइकिल वितरित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामनाएँ दीं। अंत में विद्यालय परिवार द्वारा सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया।

जनदर्शन में गूंजीं शिक्षा, सड़क,सीमांकन, आजीविका की मांगें

धमतरी। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने बीते दिन कलेक्टोरेट में आयोजित जनदर्शन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे ग्रामीणों और नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं तथा संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनदर्शन में शिक्षा, राजस्व, सड़क, आवास, सिंचाई, पेयजल, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मामले सामने आए। ग्राम पंचायत लटियारा के सरपंच ने ग्राम लटियारा में एकलव्य विद्यालय खोलने का प्रस्ताव कलेक्टर के समक्ष रखा। राजस्व से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बेलरगांव तहसील के ग्राम बिरगुड़ी निवासी होमनलाल सोनी ने बताया कि उनकी भूमि का सीमांकन दो अलग.अलग

राजस्व निरीक्षकों द्वारा किया गया, जिनकी रिपोर्ट परस्पर विरोधी है। उन्होंने जिला स्तरीय टीम गठित कर पुनः सीमांकन एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। ग्राम छुही के भारतलाल साहू ने आवेदन देकर बताया कि उनकी भूमि रामसागर जलाशय में सिंचाई विभाग की परियोजना में समाहित हो गई है। लेकिन अब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। ग्राम पंचायत मुकुंदपुर के सरपंच एवं ग्रामीणों ने घास भूमि के खसरा नंबर एवं रकबे को आवासीय बसाहट के लिए आबादी भूमि घोषित करने की मांग की। ग्रामीणों ने सड़कपारा में पाइप कनेक्शन की अनुमति देने तथा दुगलीपारा से हरदीभाठा मुख्य मार्ग तक लगभग एक किलोमीटर सीसी सड़क निर्माण के लिए राशि स्वीकृत करने का भी आग्रह किया। ग्राम पंचायत घोटगांव के ग्रामीणों ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग रखी। वहीं ग्राम पंचायत मोहेरा के राजमिस्त्री प्रशिक्षणार्थियों एवं अन्य नागरिकों ने प्रोजेक्ट उन्नति के तहत राजमिस्त्री प्रशिक्षण शुरू कराने की मांग की। पीएमश्री विद्यालयों में कार्यरत योग एवं खेल शिक्षकों ने मानदेय भुगतान में हो रही देरी का मुद्दा उठाया। दूसरी ओर ग्राम चंद्रसूर के ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना प्लस 2.0 के चयन में भेदभाव एवं पक्षपात की शिकायत दर्ज कराई। ग्राम जुगदेही निवासी हृदय रोगी तुमेश कुमार साहू ने बताया कि उनका उपचार एम्स रायपुर में चल रहा है और स्वास्थ्य कारणों से वे भारी श्रम करने में असमर्थ हैं। उन्होंने परिवार के भरण.पोषण के लिए कार्यालयीन कार्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। इसके अलावा रामसागर पारा, धमतरी निवासी भूपेश रजक ने अपने बच्चे के लिए बेहतर विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की मांग करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया। जनदर्शन के दौरान कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने सभी आवेदनों पर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई करते हुए समयसीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनदर्शन का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ समाधान सुनिश्चित करना है।

कसडोल प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच और पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग, मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

बलौदाबाजार। कसडोल थाना क्षेत्र के बहुचर्चित प्रकरण को लेकर बलौदाबाजार प्रेस क्लब ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर कुलदीप शर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। ज्ञापन की प्रतिलिपि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग सहित विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को भी प्रेषित की गई है। प्रेस क्लब ने ज्ञापन में कहा है कि कसडोल थाना क्षेत्र में सामने आए प्रकरण में एक ओर स्वयं को अनुसूचित जाति वर्ग की बताने वाली युवती द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं, वहीं दूसरी ओर थाना कसडोल पुलिस ने 28 जून 2026 को अपराध क्रमांक 260/2026 में धारा 308(2), 308(6), 217, 248(ख), 61(2)(क) एवं 45 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मामला दर्ज कर इसे कथित ब्लैकमेलिंग एवं उगाही का प्रकरण बताया है। दोनों पक्षों के दावे एक-दूसरे से भिन्न होने के कारण सत्य का पता लगाने के लिए स्वतंत्र एवं उच्चस्तरीय जांच आवश्यक है। ज्ञापन में मांग की गई है कि मामले की जांच स्थानीय स्तर

से हटाकर किसी स्वतंत्र एजेंसी अथवा वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में कराई जाए, ताकि निष्पक्ष रूप से वास्तविक तथ्य सामने आ सकें। प्रेस क्लब ने यह भी मांग की है कि प्रकरण से जुड़े महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए। इसके तहत थाना कसडोल एवं एसडीओपी कार्यालय कसडोल के 24 जून से 28 जून 2026 तक तथा कलेक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं सखी सेंटर, बलौदाबाजार के 26 जून से 28 जून 2026 तक के सीसीटीवी फुटेज संरक्षित कर जांच का हिस्सा बनाया जाए। ज्ञापन में बलौदाबाजार निवासी पत्रकार विजय शंकर तिवारी को उक्त प्रकरण में आरोपी बनाए जाने पर भी चिंता व्यक्त की गई है। प्रेस क्लब ने मांग की है कि उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष समीक्षा की जाए। साथ ही पत्रकार के साथ थाना कसडोल में कथित मारपीट के आरोपों की स्वतंत्र जांच कर दोषी पाए जाने वाले पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। प्रेस क्लब ने कहा कि लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निर्भीक पत्रकारिता की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। इसलिए छत्तीसगढ़ में लंबे समय से लंबित पत्रकार सुरक्षा कानून शीघ्र लागू किया जाए तथा पत्रकारों को उनके वैधानिक दायित्वों के निर्वहन के दौरान प्रभावी विधिक संरक्षण प्रदान किया जाए। मुख्यमंत्री के नाम यह ज्ञापन जिला कलेक्टर कुलदीप शर्मा को सौंपा गया। इस दौरान बलौदाबाजार प्रेस क्लब के अध्यक्ष नरेश गनशानी के नेतृत्व में सचिव दलजीत सिंह चावला, कोषाध्यक्ष राजेश्वर सिंह गिरी, राघवेंद्र सिंह, गोविंद रात्रे, श्रवण ध्रुव, लोकेश्वर बघेल, गणेश साहू सहित बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे। प्रेस क्लब ने उम्मीद जताई है कि शासन एवं प्रशासन इस पूरे मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी एवं न्यायसंगत कार्रवाई सुनिश्चित करेगा, जिससे सत्य सामने आए और दोषी के विरुद्ध कानून के अनुरूप कार्रवाई हो सके।

सीएम हेल्पलाइन 1076 से दिव्यांग दिव्यांग दुर्गेश साहू को मिली ट्राइसाइकिल

बलौदाबाजार। सोशल मीडिया के माध्यम से सीएम हेल्पलाइन 1076 की जानकारी मिलने के बाद बलौदाबाजार संजय कॉलोनी निवासी दिव्यांग दुर्गेश साहू ने नई ट्राई साइकिल प्रदान करने के लिए कॉल किया। इसके बाद 15 दिनों के भीतर उन्हें नई बैटरी संचालित ट्राइसाइकिल उपलब्ध करा दी गई। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने आज दुर्गेश साहू को नई बैटरी संचालित ट्राइसाइकिल प्रदान की। इस अवसर पर उन्होंने दुर्गेश से उनका हाल-चाल जाना और ट्राइसाइकिल का अनुभव भी पूछा। इस पर दुर्गेश साहू ने बताया कि ट्राइसाइकिल की गुणवत्ता काफी अच्छी है तथा इसकी ऊंचाई भी सुविधाजनक है, जिससे इसे चलाने में आसानी होगी। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने कहा कि दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिल एवं अन्य सहायक उपकरणों की मरम्मत के लिए बार-बार परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा शीघ्र ही रिपेयरिंग शॉप की स्थापना की जाएगी। इससे दिव्यांगजनों को अपने सहायक

उपकरणों की मरम्मत की सुविधा स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010 में एक सड़क दुर्घटना के कारण दुर्गेश साहू गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दुर्घटना के बाद उनके शरीर का कमर के नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर गया, जिससे वे पूर्णतः दिव्यांग हो गए। लंबे समय तक उन्हें आने-जाने सहित दैनिक कार्यों के लिए अपने परिवार पर निर्भर रहना पड़ता था। दुर्गेश साहू को पूर्व में भी समाज कल्याण विभाग द्वारा ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन समय के साथ उसके महत्वपूर्ण पार्ट्स खराब हो गए और उनकी मरम्मत संभव नहीं हो पा रही थी। इससे उनकी आवाजाही और आजीविका दोनों प्रभावित हो रही थीं। इसी दौरान उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से सीएम हेल्पलाइन 1076 की जानकारी मिली। उन्होंने हेल्पलाइन पर अपनी समस्या दर्ज कराई, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 15 दिनों के भीतर समाज कल्याण विभाग द्वारा उन्हें नई बैटरी संचालित ट्राइसाइकिल उपलब्ध करा दी गई। नई बैटरी संचालित ट्राइसाइकिल मिलने से अब दुर्गेश साहू को अपने दैनिक कार्यों के साथ-साथ अपनी छोटी सी किराना दुकान के संचालन में भी काफी सुविधा मिलेगी। इससे वे पहले की तुलना में अधिक आत्मनिर्भर होकर अपना जीवनयापन कर सकेंगे। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग की उप संचालक सिनीवाली गोयल ने दुर्गेश साहू को दिव्यांग जनों के लिए संचालित ऋण योजनाओं मो जानकारी भी दी ताकि उनको अपने व्यवसाय में मदद मिल सके। दुर्गेश साहू के पुत्र रवि कुमार साहू ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि नई ट्राइसाइकिल मिलने से उनके पिता की कई समस्याएं दूर हो गई हैं। अब उन्हें आवागमन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री एवं जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन 1076 वास्तव में आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने वाला प्रभावी मंच बन चुकी है। दुर्गेश की समस्या का यह त्वरित समाधान सुशासन और संवेदनशील प्रशासन का एक प्रेरक उदाहरण है।

किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार प्रतिबद्ध : रामविचार नेताम

धमतरी। छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विकास एवं किसान कल्याण, आदिम जाति विकास, जैव प्रौद्योगिकी, मछलीपालन तथा पशुधन विकास मंत्री रामविचार नेताम ने धमतरी जिले के प्रवास के दौरान कृषि, अनुसंधान एवं कृषक हित से जुड़े विभिन्न संस्थानों और परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, कुरूद का भ्रमण कर वहां संचालित शैक्षणिक एवं अनुसंधान गतिविधियों का अवलोकन किया तथा जिले के विभिन्न ग्रामों में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं नवाचार आधारित परियोजनाओं का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को किसानों के हित में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, कुरूद पहुंचने पर महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ नवनीत राणा ने मंत्री नेताम का स्वागत करते हुए महाविद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों, अनुसंधान परियोजनाओं, विद्यार्थियों के प्रशिक्षण तथा कृषि नवाचारों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। इस अवसर पर मंत्री

नेताम ने महाविद्यालय के विभिन्न विभागों की आधुनिक प्रयोग शालाओं, स्मार्ट क्लास रूम, डिजिटल लाइब्रेरी, प्रतियोगी परीक्षा फोरम एवं अन्य शैक्षणिक संसाधनों का निरीक्षण किया। उन्होंने छात्र.छात्राओं से संवाद कर अध्ययन व्यवस्था, शोध गतिविधियों तथा छात्रावास में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। विद्यार्थियों ने महाविद्यालय एवं छात्रावास में उपलब्ध शैक्षणिक, तकनीकी एवं आधारभूत सुविधाओं पर संतोष व्यक्त किया। मंत्री नेताम ने महाविद्यालय स्थित कृषि संग्रहालय में विद्यार्थियों द्वारा तैयार कृषि मॉडल, वैज्ञानिक प्रदर्शनी तथा मशरूम प्रसंस्कृत उत्पादों का अवलोकन किया। उन्होंने विद्यार्थियों की नवाचारपूर्ण सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास भविष्य की आधुनिक, आत्मनिर्भर एवं तकनीक आधारित कृषि व्यवस्था की मजबूत नींव हैं। इस दौरान कृषि उत्पादन आयुक्त परदेशी सिद्धार्थ कोमल ने महाविद्यालय के संकाय सदस्यों एवं विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कृषि शिक्षा में नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, कृषि अनुसंधान तथा कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप तकनीकी दक्षता विकसित करने के लिए प्रेरित किया।

कृषि एवं ग्रामीण आजीविका से जुड़े नवाचारों का किया अवलोकन

धमतरी प्रवास के दौरान मंत्री नेताम ने ग्राम मरौद में बीज प्रसंस्करण इकाई एवं नील.हरित काई उत्पादन का निरीक्षण किया। इसके पश्चात ग्राम चर्रा में मुर्गीपालन एवं बकरी पालन गतिविधियों का अवलोकन कर ग्रामीण आजीविका संवर्धन के प्रयासों की जानकारी ली। ग्राम छाती में मखाना की खेती तथा ग्राम देमार में संजय गांधी पिछड़ा हेचरी का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति एवं लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान मंत्री नेताम ने जिले के मत्स्यपालको को मछली बीज ओ भी वितरण किया।

कृषि को तकनीक, अनुसंधान से जोड़ना समय की आवश्यकता : मंत्री नेताम

इस अवसर पर मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय में वृद्धि, कृषि को लाभकारी बनाने तथा युवाओं को कृषि आधारित उद्यमिता से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आधुनिक कृषि शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, जैव प्रौद्योगिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उन्नत तकनीकों का समावेश कृषि क्षेत्र को नई दिशा देगा। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपने ज्ञान एवं शोध को खेतों तक पहुंचाकर किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम बनें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए किसानों तक आधुनिक तकनीक, गुणवत्तापूर्ण बीज, उन्नत कृषि पद्धतियों एवं वैज्ञानिक सलाह को समयबद्ध रूप से पहुंचाया जाए, ताकि कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में निरंतर वृद्धि हो सके। इस अवसर पर संचालक कृषि राहुल देव, कलेक्टर अबिनाश मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुरूद, उपसंचालक कृषि मोनेश साहू, उप संचालक पशुपालन मरकाम, सहायक संचालक उद्यानिकी गीता साहू, सहायक संचालक मछलीपालन कमल कुमार के अलावा कृषि महाविद्यालय के प्राध्यापकगण, अधिकारी.कर्मचारी, छात्र.छात्राएं तथा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

संपादकीय

नई ईवी नीति- इलेक्ट्रिक वाहनों से घटेगा प्रदूषण या बढ़ेंगी आम लोगों की मुश्किलें?

दिल्ली की सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन की बदहाली छिपी नहीं है। इसे बेहतर बनाने के लिए किसी भी सरकार ने ऐसे कदम नहीं उठाए हैं, ताकि लोग निजी वाहनों के बारे में न सोचें। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नीति के जरिए अगर दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या पर काबू पाने में मदद मिलती है, तो इसे एक बेहतर उपाय माना जाएगा। इसमें कोई दोराय नहीं कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की गहराती समस्या के मद्देनजर इसकी मुख्य वजहों की पहचान और उनसे निपटने के लिए ठोस उपाय करना जरूरी है। मगर इस क्रम में सरकार जिन नीतियों का सहारा लेना चाहती है, वे व्यापक जनहित में हों, यह सुनिश्चित किया जाना भी वक्त का तकाजा है।देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली में वायु प्रदूषण एक अहम समस्या के रूप में चिंता का मुद्दा बना रहता है। इसके लिए सड़क पर चलने वाले वाहनों को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जाता है। खासतौर पर दुपहिया वाहनों की बढ़ती संख्या न केवल सुव्यवस्थित यातायात, बल्कि प्रदूषण के लिहाज से अपेक्षया ज्यादा बहस के केंद्र में रहती है।इन्हीं बिंदुओं के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने सोमवार को नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 को मंजूरी दे दी है। नई नीति के तहत अगले वर्ष जनवरी से सिर्फ ई-ऑटो यानी इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों का ही पंजीकरण होगा। साथ ही, जनवरी 2028 से सिर्फ ई-दुपहिया वाहनों का ही पंजीकरण कराया जा सकेगा। नई नीति के तहत अब इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सड़क-कर और पंजीकरण शुल्क में छूट की व्यवस्था भी की गई है।जाहिर है, सरकार ने एक तरह से नीतिगत तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के क्रम में एक ठोस फैसला किया है, लेकिन चूंकि इसका वैसे लोगों के जीवन पर व्यापक असर पड़ने की संभावना है, जिनकी रोजी-रोटी इन वाहनों से जुड़ी होती है, इसलिए फिलहाल इसके कई अन्य पहलुओं पर बहस जारी है।हालांकि यह भी एक तथ्य है कि दिल्ली में पिछले कई वर्षों से लगातार प्रदूषण की वजह से हालात बेहद चिंताजनक होते गए हैं, तो इसमें वाहनों की खासी भूमिका रही है। मगर इसमें कारों और अन्य वाहनों के बरक्स दुपहिया और तिपहिया वाहनों की कितनी भूमिका है, इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। खासतौर पर इसलिए भी कि दिल्ली में तिपहिया वाहन आमतौर पर सीएनजी से चलते हैं। एक समय पेट्रोल और डीजल वाहनों के धुएं से होने वाला प्रदूषण व्यापक चिंता का विषय बना था और उस समय सीएनजी वाहनों के जरिए दिल्ली की हवा को स्वच्छ करने के दावे किए गए थे। लेकिन आज भी दिल्ली में वायु प्रदूषण की हकीकत किसी से छिपी नहीं है। वहीं, इलेक्ट्रिक कचरा आज विश्वभर में पर्यावरण के सामने एक नई चुनौती बन रहा है।यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि इस नीति के केंद्र में फिलहाल जिन दुपहिया और तिपहिया वाहनों को रखा गया है, वे बड़ी संख्या में साधारण लोगों की आजीविका और आवागमन का मुख्य सहारा रहे हैं। नई नीति की अनिवार्यता की स्थिति में अपने वाहन को इलेक्ट्रिक प्रणाली में बदलना कम आयवर्ग के लोगों के लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ बन सकता है।दूसरी ओर, दिल्ली की सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन की बदहाली छिपी नहीं है।

देखा जाये तो दशकों तक भारतीयों का खून बहाने वाला पाकिस्तान अब पानी की कमी होने पर कांप रहा है और वहां के नेता गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सिंधु पाकिस्तान की जीवनरेखा है और भारत पानी को हथियार बना रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान अपने पानी, अपनी संप्रभुता और अपने भविष्य की रक्षा करेगा। पाकिस्तान के जलवायु मंत्री मुसद्दिक मलिक ने तो यहां तक कह दिया कि जो हाथ उनके पानी को छुएंगे, उन्हें काट दिया जाएगा। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने भी भारत पर पानी रोकने का आरोप लगाते हुए आक्रामक बयान दिए।

पानी पाकिस्तान का बंद हुआ है, मगर गला यहां के 'शांति दूतों' का क्यों सूख रहा है?

(नीरज कुमार दुबे)

देखा जाये तो दशकों तक भारतीयों का खून बहाने वाला पाकिस्तान अब पानी की कमी होने पर कांप रहा है और वहां के नेता गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सिंधु पाकिस्तान की जीवनरेखा है और भारत पानी को हथियार बना रहा है।

पहलगाम हमले के बाद भारत ने जिस दृढ़ता के साथ पाकिस्तान को उसकी असली जगह दिखानी शुरू की है, उससे इस्लामाबाद की सत्ता, सेना और वहां के कथित लोकतांत्रिक चेहरे बुरी तरह बौखला गए हैं। सिंधु जल संधि को स्थगित करने के भारत के फैसले ने पाकिस्तान की नसों में ऐसा डर भर दिया है कि वहां के नेता लगातार धमकियां दे रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रो रहे हैं और दुनिया को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ने उनके अस्तित्व पर हमला कर दिया है।

देखा जाये तो दशकों तक भारतीयों का खून बहाने वाला पाकिस्तान अब पानी की कमी होने पर कांप रहा है और वहां के नेता गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सिंधु पाकिस्तान की जीवनरेखा है और भारत पानी को हथियार बना रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान अपने पानी, अपनी संप्रभुता और अपने भविष्य की रक्षा करेगा। पाकिस्तान के जलवायु मंत्री मुसद्दिक मलिक ने तो यहां तक कह दिया कि जो हाथ उनके पानी को छुएंगे, उन्हें काट दिया जाएगा। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने भी भारत पर पानी रोकने का आरोप लगाते हुए आक्रामक बयान दिए। पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री इशाक डार ने दुनिया को डराने की कोशिश की कि यदि सिंधु जल संधि नहीं बची तो द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की पूरी विश्व व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी।

लेकिन पाकिस्तान के इन आंसुओं के पीछे छिपा सच पूरी दुनिया जानती है। पहलगाम में 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाले आतंकवादी कहां से आए थे? जम्मू-कश्मीर में दशकों से आतंकवाद को कौन पालता रहा है? भारत के सैनिकों और नागरिकों का खून बहाने के लिए हथियार, प्रशिक्षण और धन कौन देता रहा है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल सही कहा था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करके यह स्पष्ट कर दिया कि अब नई दिल्ली पुरानी नीति पर नहीं चलेगी। यदि पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति बनाए रखेगा तो उसे हर मोर्चे पर कीमत चुकानी होगी। भारत ने पश्चिमी नदियों पर अपने अधिकार वाले जल के उपयोग को तेज करने का फैसला किया है। यह कोई युद्ध नहीं, बल्कि अपने अधिकारों का प्रयोग है।

साथ ही सबसे बड़ा सवाल उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जो भारत में बैठकर पाकिस्तान से वार्ता की मांग कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि एक सौ से अधिक तथाकथित बुद्धिजीवियों, नेताओं और सामाजिक हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाहबाज शरीफ को पत्र लिखकर बातचीत बहाल करने, वीजा सेवाएं शुरू करने, दूतावास सामान्य करने और यहां तक कि कश्मीर पर फिर से बातचीत करने की मांग की है। इस पत्र पर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मीरवाइज उमर फारूक और कुछ अन्य भारतीय हस्तियों के हस्ताक्षर भी हैं।

इन लोगों से देश पूछना चाहता है कि आखिर पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों है? जो देश भारत में आतंकवादी भेजता है, हमारे नागरिकों की हत्या करवाता है, सीमा पार से गोलियां चलाता है, उसी देश के लिए इनके दिल में इतनी बेचैनी क्यों उमड़ती है? भारत ने जब पाकिस्तान का पानी रोकने की दिशा में कदम उठाया तो प्यास पाकिस्तान को लगी, लेकिन गला यहां बैठे तथाकथित शांति दूतों का सूखने लगा। आखिर क्यों? क्या इन लोगों को भारत की सुरक्षा से ज्यादा चिंता पाकिस्तान की खेती और उसकी बिजली व्यवस्था की है?

ये लोग कहते हैं कि वार्ता ही समाधान है। लेकिन देश जानना चाहता है कि आखिर कितनी वार्ताएं हो चुकी हैं? लाहौर बस यात्रा से लेकर आगरा शिखर वार्ता तक और उफा से लेकर शरम अल शेख तक भारत ने हर बार शांति का हाथ बढ़ाया। बदले में मिला क्या? कारगिल, संसद हमला, मुंबई हमला, उरी, पुलवामा और अब पहलगाम। पाकिस्तान हर बार वार्ता की मेज पर मुस्कुराता है और पीठ पीछे आतंकियों को भेजता है।

आज जब भारत पहली बार कठोर नीति पर डटा है तो देश के भीतर बैठे कुछ लोग बेचैन हो उठे हैं। उन्हें आतंकवाद पर गुस्सा नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान का पानी रुकने पर दर्द होने लगता है। उन्हें भारत के शहीदों की चिंता कम और इस्लामाबाद की परेशानी ज्यादा दिखाई देती है। यह वही मानसिकता है जिसने दशकों तक भारत को कमजोर नीति में बांध कर रखा।

सच यह है कि सिंधु जल संधि का सबसे ज्यादा लाभ पाकिस्तान ने उठाया। भारत ने वर्षों तक उदारता दिखाई, जबकि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता रहा। अब जब नई दिल्ली ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंक और व्यापार, आतंक और वार्ता, आतंक और पानी साथ साथ नहीं चल सकते, तब पाकिस्तान दुनिया भर में सहानुभूति जुटाने निकला है। लेकिन दुनिया भी समझ रही है कि समस्या की जड़ कहां है।

पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि धमकियों से भारत डरने वाला नहीं है। पानी को लेकर युद्ध जैसे बयान देने वाले पहले अपने घर की हालत देखें। वहां की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, जनता महंगाई से त्रस्त है और सेना तथा सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए भारत विरोध का सहारा ले रही हैं।

देखा जाये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान नीति ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नया भारत अब केवल प्रतिक्रिया नहीं देगा, बल्कि अपने हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कदम भी उठाएगा। आतंकवाद को पालने वालों को अब हर क्षेत्र में जवाब मिलेगा। पाकिस्तान यदि वास्तव में शांति चाहता है तो उसे पहले आतंकवाद की फैक्टरी बंद करनी होगी। जब तक उसकी धरती से भारत विरोधी आतंक जारी रहेगा, तब तक कोई भी वार्ता केवल छलावा मानी जाएगी।

बहरहाल, भारत की जनता अब भ्रम में नहीं है। देश समझ चुका है कि शांति की सबसे पहली शर्त सुरक्षा है। और जो लोग पाकिस्तान के लिए आंसू बहा रहे हैं, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि भारत की सहनशीलता को कमजोरी समझने की भूल अब कोई नहीं कर सकता। नया भारत अपने सैनिकों के खून का हिसाब भी लेगा और अपने पानी का अधिकार भी बचाएगा।

'इच्छाधारी' आस्था का चुनावी गणित

(प्रणय विक्रम सिंह)

अयोध्या के संदर्भ में विपक्ष की नई-नई जागी श्रद्धा को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी से एक बहुत बड़ी चूक हो गई है।

वे मारीच, सुबाहु और कालनेमि जैसे दिव्य भेष बदलने वाले मायावियों को त्रेतायुग में ही निपटा गए। उन्हें जरा रुकना चाहिए था। वे आज के युग में आते, तो देखते कि भेष बदलने की यह कला अब केवल राक्षसों की बपौती नहीं रही, इसका लोकतांत्रिक विकास हो चुका है और अब इसके सबसे कुशल अभ्यासकर्ता हमारे राजनेता हैं।

सुना है, कल तक जो लोग भगवान राम को केवल एक अदालती एफेडेविट का 'काल्पनिक पात्र' मानते थे, आज वे चुनाव की आहट सुनते ही हाथ में आस्था का नया-नवेला थर्मामीटर लेकर घूम रहे हैं। वे ट्विटर पर अयोध्या को 'अनुपम और अनुकरणीय धार्मिक नगरी' बनाने की वैसी ही पवित्र कसमें खा रहे हैं, जैसी कसमें एक जेबकतरा अपनी ईमानदारी सिद्ध करने के लिए कोट कचहरी में खाता है।

इस दिव्य और त्वरित हृदय परिवर्तन को देखकर मुझे गिरगिटों की मानसिक स्थिति पर तरस आता है। बेचारे डिप्रेशन में होंगे कि जिस हुनर के लिए वे सदियों से बदनाम थे, उसमें कुछ सैफई ब्रांड समाजवादी इंसानों ने पीएचडी कर ली और उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा।

आखिर कोई उस राम-नाम का जाप इतनी पवित्रता से कैसे कर सकता है, जिसके राजनीतिक कुनबे का पूरा इतिहास ही राम-विरोध की खाद पर फला-फूला हो?

आजकल वे फीता लेकर निकले हैं। पूछ रहे हैं कि अयोध्या से गोरखपुर कितनी दूर है? नेताजी, दूरी नापने का यह शौक नया है। पर आप गलत नक्शा देख रहे हैं। अयोध्या से गोरखपुर की दूरी तो उतनी ही है, जितनी सत्य और सनातन के बीच होती है। यानी दोनों आपस में जुड़े हैं। पर आपके 'पारिवारिक सिंडिकेट' और रामराज्य के बीच की दूरी अनंत है, जिसे नापने के लिए आपके पास न तो नैतिक पैमाना है और न ही वैसा चरित्र। अच्छा होता कि आप इस दूरी को नापने से पहले यह बता पाते कि राम के प्रति आपकी खानदानी नफरत और आपके वोटबैंक के लालच के बीच कुल कितने किलोमीटर का फासला है?

जब आदमी को अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती दिखती है, तो उसे इतिहास की कड़वी यादें भूलने का 'अल्जाइमर' रोग हो जाता है। लेकिन जनता की याददाश्त बहुत क्रूर होती है, नेताजी। जनता को आज भी याद है कि जब आपके पूज्य पिताजी की हुकूमत थी, तब अयोध्या की पावन गलियों में कोई भजन नहीं गूंज रहा था, बल्कि निहत्थे रामभक्तों का खून बह रहा था। तब आपकी सरकारी मशीनरी मंदिर के पत्थरों को जब्त करने में वैसी ही मुस्तैदी दिखा रही थी, जैसी मुस्तैदी कोई डकैत माल समेटने में दिखाता है। और उसी पावन दौर में, पुलिस थानों और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी मनाने पर ऐसा प्रतिबंध था, मानो कंस खुद लखनऊ के सचिवालय में आकर बैठ गया हो।

जो लोग कल तक रामलला के प्राण-प्रतिष्ठा के निमंत्रण पत्र को अछूत मानकर ठुकरा रहे थे, आज वे 'सियाराम-धाम' के पुनरुद्धार का ठेका लेने की बात कर रहे हैं। यह वैसा ही है जैसे बिल्ली चूहों की सुरक्षा के लिए एक सर्वदलीय समिति बनाने का प्रस्ताव रखे।

राम की सेवा के लिए 'भेष' और 'ट्वीट' बदलने की नहीं, 'भाव' बदलने की जरूरत होती है। पर आपके पास तो वही पुराना हलफनामा है, जो आपने कभी सर्वोच्च न्यायालय में जमा किया था। आपकी पूरी राजनीतिक पूंजी ही यही रही है कि जब तक सत्ता में रहो, हिंदुओं की आध्यात्मिक भावनाओं को वैसे ही कुचलो जैसे रास्ते का कंकड़ कुचला जाता है, और जब चुनाव आ जाएं, तो माथे पर एक लंबा सा छद्म टीका लगाकर 'इच्छाधारी रामभक्त' की मुद्रा में जनता को सम्मोहित करने निकल पड़ो।

मेरी की एक बात हमेशा याद रखिएगा भैयाजी, आप भगवान को धोखा दे सकते हैं क्योंकि वे घट-घट वासी होकर भी चुप रहते हैं, पर जनता को नहीं, क्योंकि वह सब देखकर सही समय पर ईवीएम का बटन दबाती है।

सुना है, आपने तो अयोध्या का राजा ही बदल दिया। जबकि सभी सनातनियों के लिए त्रेता युग से आज तक अयोध्या के राजा श्री रामचन्द्र जी हैं। जो काम लंका का रावण अपनी पूरी दस खोपड़ियों की ताकत लगाकर नहीं कर पाया, वह आपने अपने वोटबैंक को खुश करने के लिए बड़ी सरलता से कर दिया। कई दिनों तक संसद में अपने बगल में उनको बैठाकर घुमाते रहे। राम से इतनी घृणा कि उन्हें अयोध्या के राजा के रूप में स्वीकार करने में आपकी छाती फटने लगती है, इसलिए आपने प्रतीकों का नया बाज़ार सजा लिया। आपका यह दोहरा चरित्र और अतीत उत्तर प्रदेश के हर रामभक्त के सीने में एक गहरे घाव की तरह आज भी टीस रहा है।

याद रखिए, इतिहास की स्याही बहुत पक्की होती है, वह आपके इन बनावटी और सुगठित ट्वीट्स के 'थूक' से नहीं धुलेगी। 10 नवंबर 1990 का वह अंधकारमय काला दिन, निहत्थों का रक्तपात, थानों में जन्माष्टमी पर पाबंदी और पावन पत्थरों का अपमान, यह सब आपके माथे पर वो अमिट कलंक हैं, जिन्हें धोने के लिए यदि आप सरयू का पूरा पानी भी इस्तेमाल कर लें, तो भी कम पड़ेगा।

अयोध्या अब सज चुकी है, दिव्य और भव्य हो चुकी है। वहां अब आपके पाखंड का कोहरा नहीं, बल्कि प्रभु राम का 'परम प्रकाश' जगमगा रहा है। और इतिहास गवाह है कि जब प्रकाश उदित होता है।

ग्राम्य विकास के विरोध में विपक्ष !

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का हालिया निर्णय, जिसमें ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने की व्यवस्था को असंवैधानिक ठहराया गया है, इसी समीक्षा की एक स्वाभाविक परिणति है। लेकिन यहां सहमति और असहमति के विकल्प भी हैं। संविधान में असहमति के बिंदु पर आगे जाने की व्यवस्था भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यों को केंद्र में रखते हुए यह फैसला लिया था तो वह अपने संविधान सम्मत विकल्प भी देखेगी। लेकिन विपक्ष जिस प्रकार इस न्यायिक निर्णय को राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए आतुर है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य सरकार ने एक प्रयास किया था कि किसी भी अवरोध पर गांवों का विकास अवरुद्ध न होने पाए।

(सुरेश बहादुर सिंह)

उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में ग्राम प्रधानों को भयभीत कर विपक्ष न सिर्फ नकारात्मक राजनीति का उदाहरण पेश कर रहा है, बल्कि ग्रामीण विकास में बाधा भी बन रहा है। यह साबित करता है कि जनाधार खो चुके राजनीतिक दल अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।)

एक बड़ा प्रश्न हम सबके समक्ष है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? जवाब बहुत सारे हो सकते है, जैसे कि जनादेश सबसे बड़ी शक्ति है लेकिन बात पूरे लोकतंत्र की हो रही है। जनादेश यह तय करता है कि सत्ता किसकी होगी लेकिन जब लोकतंत्र के बारे में विचार करेंगे तो उसकी असली ताकत संविधान द्वारा निर्धारित संस्थाओं के बीच संतुलन और परस्पर सम्मान के रूप में उभरकर सामने आएगी। शासन जनता के विश्वास से चलता है, किंतु उसकी वैधता संविधान से आती है। इसलिए जब न्यायपालिका किसी प्रशासनिक निर्णय की संवैधानिक समीक्षा करती है, तो वह किसी सरकार की पराजय या विपक्ष की विजय का अवसर नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्वाभाविक प्रक्रिया है। दुर्भाग्य से आज न्यायालयों के निर्णय भी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनते जा रहे हैं। फैसलों की कानूनी व्याख्या से अधिक उन्हें राजनीतिक लाभ-हानि के तराजू पर तौला जा रहा है, जिससे समाज में भ्रम और अविश्वास का वातावरण पैदा होता है। ऐसी परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि न्यायिक निर्णयों को उनकी संवैधानिक भावना के अनुरूप समझा जाए, न कि राजनीतिक प्रचार के औजार के रूप में देखा जाए।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का हालिया निर्णय, जिसमें ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने की व्यवस्था को असंवैधानिक ठहराया गया है, इसी समीक्षा की एक स्वाभाविक परिणति है। लेकिन यहां सहमति और असहमति के विकल्प भी हैं। संविधान में असहमति के बिंदु पर आगे जाने की व्यवस्था भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यों को केंद्र में रखते हुए यह फैसला लिया था तो वह अपने संविधान सम्मत विकल्प भी देखेगी। लेकिन विपक्ष जिस प्रकार इस न्यायिक निर्णय को राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए आतुर है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य सरकार ने एक प्रयास किया था कि किसी भी अवरोध पर गांवों का विकास अवरुद्ध न होने पाए। जो विकास कार्य चल रहे हैं, वे रुकने न पाएं। इसमें सरकार का अपना पक्ष विकास का है।

न्यायालय का अपना पक्ष है, लेकिन इसी के साथ एक बड़ा प्रश्न इस बात का भी है कि विपक्ष के दायित्व क्या होने चाहिए थे। न्यायालय की गरिमा का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जब बात विकास की हो, ग्रामीण जनता के विकास की हो तो विपक्ष का उसमें राजनीतिक स्वार्थ देखना कितना न्यायोचित है, इस पर विचार करना होगा। ऐसे मुद्दों पर संकीर्णता को त्याग कर सरकार का सहयोग देना भी विपक्ष का लोकतांत्रिक कर्तव्य है। लेकिन, न्यायालय के आदेश को सही रूप में जनता तक पहुंचाने के बजाय विपक्ष ने भ्रम, भय और असत्य का एक ऐसा जाल बुनना शुरू कर दिया, जो न ग्राम प्रधानों के हित में है, न ग्रामीण समाज के और न ही इस देश के लोकतंत्र के।

यह समझना आवश्यक है कि विपक्ष कौन से भ्रम फैला रहा है और वास्तविकता क्या है। पहला और सबसे बड़ा भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि राज्य सरकार ने जानबूझकर असंवैधानिक कार्य किया। विपक्ष की मंशा यह स्थापित करने की है कि सरकार संविधान का उल्लंघन करने की मंशा से काम कर रही थी, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? नहीं, सरकार ने वही किया जो कोई भी जिम्मेदार व सजग संस्था करती। क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए ग्राम प्रधान को ही प्रशासक बनाना सर्वाधिक उपयुक्त निर्णय था। फैसले की संवैधानिक व्याख्या एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है।

सरकारें प्रशासनिक निर्णय लेती हैं, न्यायालय उनकी संवैधानिक समीक्षा करता है और यदि न्यायालय किसी व्यवस्था को संविधान के अनुरूप नहीं पाता तो सरकार उस आदेश को स्वीकार करते हुए आवश्यक कदम उठाती है या अपने पक्ष को उचित मानते हुए बड़ी बेंच या शीर्ष अदालत तक जाती है। यही संवैधानिक लोकतंत्र की सुंदरता है और यही उसकी ताकत भी। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच यह संतुलन हमारे संविधान की आत्मा है। जब न्यायालय किसी व्यवस्था की संवैधानिक समीक्षा करता है तो इसका अर्थ यह है कि संवैधानिक व्याख्या का एक नया आयाम सामने आया है। आप सहमत हों तो स्वीकार करें या फिर इसे चुनौती दें।

कोर्ट के आदेश को केंद्र में रखते हुए एक भ्रम यह भी फैलाया जा रहा है कि ग्राम प्रधानों द्वारा किए गए अब तक के सभी कार्य और भुगतान अवैध हो गए हैं। इसे इतने जोर-शोर से फैलाया जा रहा है मानो पिछले पांच सालों में गांवों में हुआ हर निर्माण कार्य, हर सड़क, हर नाली, हर सामुदायिक भवन अब गैरकानूनी हो गया हो। यह न केवल कानूनी दृष्टि से निराधार है, बल्कि अत्यंत गैरजिम्मेदाराना भी है। जब बात गांव के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की हो रही हो, तो उसमें विपक्ष का दायित्व है कि वह सकारात्मक रुख अपनाए। इसे राजनीतिक मुद्दे के रूप में उठाने को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। राजनीतिक अटकलबाजी में वास्तविक तथ्यों की अनदेखी नहीं की जा सकती।

इस संदर्भ में एक और बात महत्वपूर्ण है जिसे विपक्ष सायास खड़ा कर रहा है। वह यह कि ग्राम प्रधानों से उनके कार्यकाल में खर्च किए गए धन की वसूली की जाएगी। विपक्ष यह भ्रम फैलाकर उन हजारों ग्राम प्रधानों के मन में भय व आतंक का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहा है, जिन्होंने ईमानदारी से अपने गांवों की सेवा की है। जो प्रतिनिधि सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने में लगे रहे, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर स्वच्छ भारत मिशन तक को गांव-गांव पहुंचाने में अपना योगदान दिया, उन्हें भयभीत करना राजनीतिक दुर्भावना की पराकाष्ठा है।

एक सहज सवाल स्वाभाविक है कि विपक्ष यह भ्रम और भय क्यों फैला रहा है? इसके उत्तर में उन लोगों की प्रवृत्ति को देखना होगा, जिन्हें जनता खारिज कर चुकी है। जिन दलों के पास न कोई रचनात्मक नीति हो, न जनता के विकास का कोई ठोस दृष्टिकोण और न ही सत्ता में रहते हुए ग्रामीण उत्थान का कोई उल्लेखनीय इतिहास हो, उन्हें अदालती आदेश में अपने लिए संभावनाएं नजर आ रही हैं। अपने संकीर्ण स्वार्थ के लिए वे इसे भुनाने की चेष्टा करना चाहते हैं। ग्रामीण लोगों को भ्रमित करके यह सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है कि सरकार उनकी विरोधी है। वास्तविकता सबके सामने है। योगी सरकार में पंचायती राज संस्थाएं कितनी सशक्त हुई हैं, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं। अदालत के आदेश पर कोई असंतुलित प्रतिक्रिया न देना न्यायपालिका के प्रति सरकार के सम्मान भाव का परिचायक है और वह इसके लिए प्रतिबद्ध भी प्रतीत होती है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के पास बड़ी बेंच या शीर्ष अदालत में अपील का अधिकार भी है। पंचायतों के विकास कार्य किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होने दिए जाएं, यह उसकी प्रतिबद्धता भी है।

लोकतंत्र में न्यायालय की भूमिका संविधान के संरक्षक की है। जब वह किसी व्यवस्था की समीक्षा करता है और उसे परिमार्जित करने का निर्देश देता है, तो यह लोकतंत्र की जीवंतता का प्रमाण है। संवैधानिक संस्थाओं का सक्रिय रहना, सजग रहना, यह संदेश देता है कि वे अपने दायित्व निभा रही हैं। न्यायालय का सम्मान, संविधान की रक्षा और गांवों का निर्बाध विकास। इन तीनों को एक साथ चलना चाहिए और इसे सुनिश्चित करना सबकी जिम्मेदारी है। सुशासन न्यायपालिका का सम्मान करता है और जनता के हितों की सुरक्षा भी। इसलिए माना जा सकता है कि सरकार सुसंगत फैसले लेगी, संविधान सम्मत लेगी, जो विपक्ष के भ्रमजाल का जवाब भी होगा। (लेखक पूर्व अपर शासकीय अधिवक्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट) ऊपर व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं।

संक्षिप्त समाचार

4.56 करोड़ के गांजा तस्करी तस्करी मामले में ओडिशा से मुख्य सप्लायर गिरफ्तार

रायपुर। छत्तीसगढ़ की महासमुंद पुलिस ने अंतरराज्यीय गांजा तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4.56 करोड़ रुपये की गांजा तस्करी के मुख्य सप्लायर को ओडिशा से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, 912.760 किलोग्राम गांजा की इस खेप का मुख्य सप्लायर मिश्रो नायक (28), निवासी कंधमाल (ओडिशा) को 1 जुलाई को बालिगुड़ा से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक, 17 अप्रैल 2026 को बसना थाना पुलिस ने पलसापाली बैरियर पर नाकाबंदी के दौरान एक आयशर मालवाहक ट्रक को पकड़ा था। ट्रक में कच्चे केले की आड़ में 29 प्लास्टिक बोरियों में छिपाकर 912.760 किलो गांजा उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा था। तस्कर पुलिस को चकमा देने के लिए वाहन पर फर्जी नंबर प्लेट का भी इस्तेमाल कर रहे थे। जांच के दौरान तकनीकी विश्लेषण और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पूरे तस्करी नेटवर्क का खुलासा हुआ। पुलिस ने पहले इस मामले के मास्टरमाइंड विनय शर्मा उर्फ पंडित जी, मुख्य बिचौलिया रामजी ठाकुर, गांजा सप्लायर रमाकांत बेहरा और बबलू नायक तथा वाहन चालक अब्दुल नईम को गिरफ्तार किया था। अब मुख्य सप्लायर मिश्रो नायक की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने तस्करी नेटवर्क की अहम कड़ी भी जोड़ ली है। गांजा तस्करी सिंडिकेट को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। मामले में पहले ही 912.760 किलोग्राम गांजा, आयशर मालवाहक वाहन और चार फर्जी नंबर प्लेट जब्त की जा चुकी हैं, जिनकी कुल अनुमानित कीमत 4 करोड़ 56 लाख। 38 हजार रुपये आंकी गई है। महासमुंद पुलिस का कहना है कि नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ 'सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक' कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच की जा रही है।

शराब दुकान से 7 लाख की चोरी का खुलासा, राजस्थान के 4 बदमाश गिरफ्तार

रायपुर। राजधानी रायपुर के आमानाका थाना क्षेत्र स्थित सरोना की कम्पोजिट विदेशी शराब दुकान में हुई लाखों रुपये की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और आमानाका थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में राजस्थान के 4 अंतरराज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में एक अन्य आरोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक, 14 जून 2026 की सुबह शराब दुकान का ताला टूटा मिला। जांच करने पर पता चला कि चोर दुकान का लॉकर ही उखाड़कर ले गए, जिसमें 7,05,580 रुपये की बिक्री राशि रखी थी। इसके अलावा करीब 10,820 रुपये मूल्य की शराब और सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी चोरी कर लिया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम गठित की। करीब 15 दिनों तक सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों के फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया। जांच के दौरान आरोपियों की लोकेशन राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मिली, जिसके बाद पुलिस टीम ने वहां दबिश देकर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि उनके एक साथी ने पहले रायपुर आकर शराब दुकान की रेकी की थी। इसके बाद सभी आरोपी योजना बनाकर चारपहिया वाहन से रायपुर पहुंचे और चोरी की वारदात को अंजाम देकर वापस राजस्थान फरार हो गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पवन कुमार पाटीकर, प्रकाश मईडा, सुनील चरपोटा और राम सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की नगदी 2 लाख रुपये, वारदात में इस्तेमाल वाहन और 4 मोबाइल फोन समेत करीब 15.50 लाख रुपये का मशरूका बरामद किया है।

शादी का झांसा देकर रिटायर्ड टेक्नीशियन से 9.50 लाख की ठगी, ओडिशा के 3 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। राजधानी रायपुर में शादी का झांसा देकर एक सेवानिवृत्त टेक्नीशियन से 9.50 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और आजाद चौक थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ओडिशा के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार, प्रार्थी मनहरण टिकरिहा की पहचान दिल्ली के एक मैरिज ब्यूरो के माध्यम से खुद को कोरबा निवासी और रेलवे इंजीनियर से सेवानिवृत्त बताने वाली रजनी शर्मा नाम की महिला से हुई थी। बातचीत के दौरान महिला ने शादी का भरोसा दिलाया और फिर पारिवारिक कार्यक्रम, दुर्घटना, इलाज समेत विभिन्न बहाने बनाकर अलग-अलग किश्तों में करीब 9.50 लाख रुपये अपने बैंक खातों में जमा करा लिए। रकम मिलने के बाद महिला ने अपना मोबाइल बंद कर दिया। शिकायत मिलने पर आजाद चौक थाना में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 111(1), 3(5) तथा आईटी एक्ट की धारा 66-डी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने मोबाइल नंबरों और बैंक खातों का तकनीकी विश्लेषण किया, जिससे आरोपियों की लोकेशन ओडिशा के बलांगीर जिले में मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने ओडिशा में दबिश देकर जसवंत डूण्डी, मनोज राणा और यश नायक को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर ठगी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मामले से संबंधित तीन मोबाइल फोन जब्त किए हैं।

हत्या के प्रयास मामले में फरार 2 आरोपी गिरफ्तार अन्य आरोपियों की तलाश जारी

रायपुर। राजधानी रायपुर में हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा आजाद चौक थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दोनों आरोपियों को दबोचा गया। मामले में अन्य फरार आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस के अनुसार, थाना आजाद चौक में वर्ष 2025 में दर्ज हत्या के प्रयास के प्रकरण में घटना के बाद से कई आरोपी फरार थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए वे लगातार अपने ठिकाने बदल रहे थे। लंबित गंभीर मामलों की समीक्षा के दौरान पुलिस उपायुक्त (क्राइम एवं साइबर) स्मृतिक राजनाला और पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) संदीप पटेल के निर्देश पर आरोपियों की तलाश तेज की गई। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और आजाद चौक थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर तंत्र सक्रिय किया, तकनीकी विश्लेषण किया और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी।

अत्याधुनिक तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का महत्व बढ़ा

चिकित्सा में आधुनिक तकनीक के साथ मानवीय संवेदनाएं भी जरूरी है

रायपुर/ संवाददाता

राज्यपाल श्री रमेन डेका ने डॉक्टर्स डे के अवसर पर आज विमतारा भवन में सिक्ख समाज छत्तीसगढ़ एवं जेसीआई रायपुर मेडिको सिटी द्वारा आयोजित अलग-अलग कार्यक्रमों में चिकित्सकों का सम्मान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था में अत्याधुनिक तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का महत्व बढ़ा है, लेकिन रोगी के प्रति मानवीय संवेदनाएं, आत्मीय व्यवहार और नैतिक मूल्यों के साथ की गई चिकित्सा ही समाज का विश्वास मजबूत करती है। राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टर का मधुर व्यवहार कई दवाइयों से भी अधिक प्रभावी होता है। मरीज के लिए चिकित्सक भगवान के समान होता है और उसे वास्तविक संतोष तभी मिलता है, जब डॉक्टर स्वयं उसका शारीरिक परीक्षण कर उसकी स्थिति को समझे। उन्होंने कहा कि आधुनिक जांच तकनीकों का अपना महत्व है, लेकिन मरीज का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपचार भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन फैमिली डॉक्टर अथवा पड़ोस के डॉक्टर की परंपरा धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है। इस परंपरा को बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि ऐसे चिकित्सक परिवारों के स्वास्थ्य और विश्वास का महत्वपूर्ण आधार होते हैं। राज्यपाल ने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चिकित्सक इस दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाकर अनेक रोगों की रोकथाम की जा सकती है। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य को वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताते हुए कहा कि चिकित्सकों को इस दिशा में विशेष ध्यान देना होगा। मोबाइल और इंटरनेट की बढ़ती लत पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इनका उपयोग केवल आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। एआई अनेक क्षेत्रों में उपयोगी है, लेकिन मानव मस्तिष्क की संवेदनशीलता, विवेक और निर्णय क्षमता का कोई विकल्प नहीं हो सकता। राज्यपाल ने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को सोचनीय बताते हुए कहा कि नशे की लत से ग्रस्त लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हुए उनका उपचार और पुनर्वास सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने सिक्ख समाज द्वारा किए जा रहे सामाजिक एवं सेवा कार्यों की सराहना भी की। राज्यपाल ने सिक्ख समाज के कार्यक्रम में समाज के चिकित्सकों तथा जेसीआई रायपुर मेडिको सिटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले चिकित्सकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, जेसीआई रायपुर मेडिको सिटी के अध्यक्ष डॉ. निखिल मोती रामानी, सचिव डॉ. अविनाश तिवारी, सिक्ख समाज के अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह छाबड़ा, एम्स रायपुर के निदेशक डॉ. अशोक जिंदल, रिम्स के निदेशक डॉ. कृष्ण कुमार वाधवा, वरिष्ठ चिकित्सक, सिक्ख समाज के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 बनी उम्मीद की किरण-एक सप्ताह में बना आयुष्मान कार्ड..

- हितग्राही ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का जताया आभार

रायपुर/ संवाददाता

शासन की योजनाओं का लाभ समय पर आम नागरिकों तक पहुँचे और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो-मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की इसी सुशासन की सोच को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 लगातार साकार कर रही है। मनेंद्रगढ़ निवासी अभिनव द्विवेदी की कहानी इसका जीवंत उदाहरण है, जहाँ एक शिकायत ने महज़ एक सप्ताह में उनकी चिंता को राहत में बदल दिया। काफी समय से आयुष्मान कार्ड नहीं बनने के कारण अभिनव द्विवेदी शासन की निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे थे। आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद कार्ड जारी नहीं होने से वे परेशान थे। अंततः उन्होंने अपनी समस्या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर दर्ज कराई और समाधान की उम्मीद जताई। शिकायत प्राप्त होते ही प्रकरण को स्वास्थ्य विभाग के पास भेजा गया। विभाग ने मामले को प्राथमिकता से लेते हुए आवश्यक परीक्षण एवं कार्रवाई की। लगातार मॉनिटरिंग और त्वरित प्रयासों के परिणामस्वरूप सिर्फ एक सप्ताह के भीतर अभिनव द्विवेदी का आयुष्मान कार्ड बनकर तैयार हो गया। आयुष्मान कार्ड बनने के साथ ही अभिनव अब आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमारी की स्थिति में आर्थिक बोझ

से भी राहत मिलेगी। शिकायत के निराकरण के बाद मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से जब अभिनव से फीडबैक लिया गया, तो उन्होंने बताया कि उनकी समस्या का पूरी तरह समाधान हो चुका है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की तत्परता की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें इतनी शीघ्र कार्रवाई की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, स्वास्थ्य विभाग तथा जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन वास्तव में आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान का भरोसेमंद माध्यम बन चुकी है। यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 केवल शिकायत दर्ज करने का मंच नहीं, बल्कि आमजन की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी और संवेदनशील समाधान का प्रभावी माध्यम है। जिला प्रशासन द्वारा सभी विभागों को शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और सुशासन की भावना निरंतर सशक्त होती रहे।

कृत्रिम गर्भाधान से पशुधन विकास की मिसाल बना ग्राम पुरी

- कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने उन्नत वत्स प्रदर्शनी का किया अवलोकन, विभागीय नवाचारों की सराहना

रायपुर/ संवाददाता

कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने धमतरी जिले के प्रवास के दौरान पशुधन विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर पशुधन विकास विभाग द्वारा विकासखंड धमतरी के मुख्य ग्राम योजना अंतर्गत ग्राम पुरी स्थित पशु चिकित्सा संस्था मुख्य ग्राम इकाई में उन्नत वत्स प्रदर्शनी कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर गायों को हरा चारा भी खिलाया । प्रदर्शनी में कृत्रिम गर्भाधान तकनीक से उत्पादित 42 उन्नत वत्सों (एफ-1 से एफ-3 पीढ़ी) का प्रदर्शन किया गया। मंत्री श्री नेताम ने उन्नत नस्ल के इन वत्सों का अवलोकन कर विभाग द्वारा किए जा रहे वैज्ञानिक एवं नवाचार आधारित प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से पशुधन की गुणवत्ता में सुधार कर दुग्ध उत्पादन बढ़ाना किसानों और पशुपालकों की आय वृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अतिथियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए पशुपालकों से संवाद किया तथा विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर कृषि उत्पादन आयुक्त श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी तथा पशुधन विकास विभाग के संचालक श्री चन्द्रकांत वर्मा, कलेक्टर श्री अविनाश मिश्रा भी उपस्थिति थे। ग्राम की सरपंच श्रीमती कुंती देवदास एवं दुग्ध सहकारी समिति के अध्यक्ष श्री चिरौंजीलाल साहू ने बताया कि ग्राम पुरी में शत-प्रतिशत कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से लगभग प्रत्येक परिवार डेयरी गतिविधियों से जुड़ चुका है। वर्तमान में ग्राम के दुग्ध संकलन केन्द्र में प्रतिदिन 500 लीटर से अधिक दूध का संकलन किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ग्राम पुरी अब वैज्ञानिक पशुपालन एवं डेयरी विकास का प्रेरणादायी मॉडल बनकर उभर रहा है। कार्यक्रम के दौरान कृत्रिम गर्भाधान कार्य में सूचना-तंत्र के रूप में महत्वपूर्ण सहयोग देने वाले ग्राम के चरवाहों को मंत्री श्री नेताम ने गमछा एवं श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया।

125 दिनों के रोजगार से बढ़ी उम्मीदें

विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन बना ग्रामीणों का नया संबल

- रोजगार अवधि बढ़ने एवं मजदूरी में वृद्धि से ग्रामीण परिवारों को मिलेगा आर्थिक सशक्तिकरण, सुनीता साहू ने जताई खुशी

रायपुर/ संवाददाता

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आजीविका और समग्र विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन से गांवों में नई उम्मीद जगी है। इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना है। योजना के तहत अब प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रति वित्तीय वर्ष 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों के अकुशल श्रम आधारित रोजगार की गारंटी दी जाएगी। साथ ही मजदूरी दर में भी वृद्धि की गई है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय में इजाफा होगा। मुंगेली जिले के ग्राम लिम्हा की सुनीता साहू ने योजना के प्रति प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि रोजगार के दिनों में वृद्धि ग्रामीण परिवारों के लिए बड़ी राहत है। पहले 100 दिनों तक ही रोजगार उपलब्ध होता था, लेकिन अब अतिरिक्त दिनों के रोजगार से परिवार की आय बढ़ेगी और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में आसानी होगी। उन्होंने बताया कि बढ़ी हुई मजदूरी और अतिरिक्त रोजगार के अवसर से अब परिवार को अधिक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। इससे बच्चों की शिक्षा, घरेलू आवश्यकताओं और अन्य खर्चों को पूरा करने में भी सहूलियत होगी।

नूतन इस्पात फैक्ट्री में करंट लगने से मजदूर की मौत, दो घायल

रायपुर। रायपुर जिले के धरसींवा विधानसभा क्षेत्र स्थित जरौदा की नूतन इस्पात फैक्ट्री में बड़ा औद्योगिक हादसा हो गया। काम के दौरान करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दो अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार, फैक्ट्री में काम के दौरान तीन मजदूर अचानक करंट की चपेट में आ गए। हादसे के बाद उन्हें तत्काल एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान अनिल यादव ने दम तोड़ दिया। वहीं, दो अन्य घायल मजदूरों का उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में फैक्ट्री पहुंचे और मुख्य गेट के सामने धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया।

अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने

रिक्त पदों की भर्ती और बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के दिए निर्देश

- महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं का गोंडी एवं हल्बी भाषा में होगा व्यापक प्रचार-प्रसार
- बस्तर प्रवास के अनुभवों के आधार पर मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने ली उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

रायपुर/ संवाददाता

महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने मंत्रालय महानदी भवन में महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक लेकर विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने तथा जमीनी स्तर पर कार्यों में गति लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार,दोनों विभागों के संचालक सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने हाल ही में बस्तर संभाग के प्रवास तथा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी से हुई चर्चा के दौरान प्राप्त अनुभवों और सुझावों के आधार पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्थानीय भाषाओं में संवाद अत्यंत आवश्यक है। इस उद्देश्य से बस्तर संभाग में विभागीय योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार गोंडी एवं हल्बी भाषा में किए जाने के निर्देश दिए गए, ताकि प्रत्येक पात्र हितग्राही तक योजनाओं की सटीक जानकारी पहुंच सके। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने बस्तर संभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं पर्यवेक्षक के रिक्त पदों को आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर शीघ्र भरने की प्रक्रिया में

तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने दूरस्थ क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केंद्रों में भवन, पोषण, पेयजल, स्वच्छता एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया। बैठक में उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए सभी जिलों में नियमित मॉनिटरिंग, सतत निरीक्षण और प्रभावी फॉलोअप सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करने की अपेक्षा व्यक्त की। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने पोषण पुनर्वास केंद्रों (एनआरसी) में भर्ती बच्चों एवं उनकी माताओं को गुणवत्तापूर्ण उपचार, पौष्टिक आहार तथा बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए कहा कि कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। समीक्षा बैठक के दौरान समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की भी विस्तृत समीक्षा की गई। मंत्री ने दिव्यांगजन एवं वृद्धजन कल्याण से संबंधित योजनाओं की प्रगति का आकलन करते हुए बस्तर संभाग में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों के समयबद्ध वितरण, पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने तथा नियमित शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए।उन्होंने सियान गुड़ी (डे-केयर सेंटर) एवं वृद्धाश्रमों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर आवास, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएं तथा सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक के अंत में मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि बस्तर संभाग के प्रवास के दौरान यह स्पष्ट रूप से अनुभव हुआ है कि क्षेत्र में विकास और विश्वास का नया वातावरण निर्मित हुआ है। ऐसे में विभाग की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है कि शासन की प्रत्येक जनकल्याणकारी योजना तीव्र गति से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और उसका प्रभाव धरातल पर दिखाई दे।

संक्षिप्त समाचार

रात के अंधेरे में तोड़फोड़ करने वाले माफ करने लायक नहीं : बृजमोहन अग्रवाल

रायपुर। नकटी गांव में बेदखली की कार्रवाई को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस बीच सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा है कि रात के अंधेरे में पहुंचकर तोड़फोड़ करना पूरी तरह गलत है और ऐसा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।सांसद बृजमोहन ने कहा कि मुझसे बातचीत के बाद भी जो लोगों के घरों में तोड़फोड़ की गई वह किसी भी हालत में माफ करने लायक नहीं है। रात के अंधेरे में इस तरह की कार्रवाई करना गलत है। जिन अधिकारियों ने यह दुस्साहस किया है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।उन्होंने कहा कि नकटी गांव के लोगों का मामला बेहद संवेदनशील है और वह अपने पहले के स्टैंड पर कायम हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि गांव के लोगों को नहीं हटाया जाना चाहिए। उनकी समस्याओं का मानवीय दृष्टिकोण से समाधान निकाला जाना चाहिए।सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने यह भी कहा कि जिस विषय को जहां रखना होता है मैं वहां अपनी बात रखता हूं। नकटी गांव में बेदखली की कार्रवाई को लेकर पहले से ही स्थानीय लोगों में नाराजगी है। वहीं अब इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है।

उच्च जोखिम वाली 1786 गर्भवती महिलाओं का हुआ नि:शुल्क सोनोग्राफी

रायपुर। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान अंतर्गत जिले में गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक माह की 9 एवं 24 तारीख को विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाता है। शिविर में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का नि:शुल्क जांच, उपचार एवं परामर्श प्रदान करना है। अभियान अंतर्गत पहला प्रसव ऑपरेशन से हुआ हो, पहले गर्भपात या मृत शिशु का जन्म हुआ हो, जिनका वजन या ऊंचाई कम हो, कम उम्र में गर्भधारण किया हो, गंभीर एनीमिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह या अन्य बीमारी से ग्रसित महिलाओं की जांच की जाती है। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की सूची बनाकर प्रत्येक सप्ताह फोन कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एवं सलाह दी जा रही है। प्रसव के 15 दिन पूर्व गर्भवती माताओं के घर प्रतिदिवस मितानिनों द्वारा भ्रमण किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेतराम नवरतन ने बताया कि वर्तमान में 1958 उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं में 1786 का प्रथम सोनोग्राफी तथा 1380 महिलाओं का द्वितीय बार सोनोग्राफी किया जा चुका है। इस सप्ताह कुल 104 उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का सोनोग्राफी किया गया।

रायपुर में मारपीट, अवैध शराब और चाकूबाजी के मामलों में पुलिस की कार्रवाई, कई आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। राजधानी रायपुर में अलग-अलग थाना क्षेत्रों में मारपीट, गाली-गलौज, अवैध शराब बिक्री और अवैध हथियार रखने के मामलों में पुलिस ने कई प्रकरण दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार, मोवा, सरस्वती नगर, खम्हारडीह, पुरानी बस्ती और टिकरापारा थाना क्षेत्रों में आपसी विवाद, जमीन बंटवारे, लेन-देन और घरेलू विवाद को लेकर मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं। आरोपियों ने पीड़ितों के साथ गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्कों व पत्थर से हमला कर घायल कर दिया। सभी मामलों में संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद के दौरान पति द्वारा पत्नी के साथ मारपीट का मामला भी दर्ज किया गया है। वहीं गुढ़ियारी थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।

चेतना विरुद्ध नशा' अभियान के तहत सीपत पुलिस की कार्रवाई, 8 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ युवक गिरफ्तार

रायपुर। बिलासपुर जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे 'चेतना विरुद्ध नशा' अभियान के तहत सीपत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को 8 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी को आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देशन में 2 जुलाई 2026 को सीपत पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम भिल्मी में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान आरोपी शेखर वर्मा (22 वर्ष), निवासी ग्राम भिल्मी, थाना सीपत, जिला बिलासपुर के कब्जे से 8 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1,600 रुपये बताई गई है।

सहकारिता मंत्रालय के पांच वर्ष पूर्ण होने पर राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन आयोजित

सहकारिता से बढ़ेगी किसानों की आय विकसित छग की नींव होगी मजबूत....

- पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, वनोपज, मत्स्य पालन और ग्रामीण उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में भी सहकारिता को मिल रहा है बढ़ावा
- किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता का सबसे प्रभावी माध्यम बन रही है सहकारिता

रायपुर/ संवाददाता

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय का गठन देश के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय है। यह निर्णय 'सहकार से समृद्धि' के संकल्प को साकार करने वाला है। डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में सहकारिता के माध्यम से किसानों, वनवासियों, महिला समूहों और ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने तथा उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मंडपम में भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के पांच वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन एवं सहकारी सप्ताह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर उत्कृष्ट समितियों को सहकार प्रेरणा पुरस्कार प्रदान किया तथा संग्रहण वर्ष 2023 के 7.14 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए 162 करोड़ रुपये से अधिक की प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि के वितरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं और बचपन से ही सहकारिता से मेरा गहरा रिश्ता रहा है। तभी से मुझे विश्वास था कि सहकारिता के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'सहकार से समृद्धि' का वही सपना धरातल पर साकार होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रथम कार्यकाल में उन्हें राज्यमंत्री के रूप में साथ काम करने का अवसर मिला और उन्होंने किसानों के प्रति प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता तथा समर्पण को बहुत करीब से देखा है। किसानों के कल्याण के प्रति इसी प्रतिबद्धता के कारण प्रधानमंत्री ने कृषि मंत्रालय का दायरा बढ़ाते हुए उसका नाम 'कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय' किया, ताकि किसानों का समग्र विकास सरकार की प्राथमिकता बने। सहकारिता किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता का सबसे प्रभावी माध्यम बन रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा मिली है और इसका लाभ सीधे किसानों एवं ग्रामीण परिवारों तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि केंद्र सरकार केवल कृषि ही नहीं बल्कि पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, वनोपज, मत्स्य पालन और ग्रामीण उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में भी सहकारिता को मजबूत कर रही है।

हत्या को आत्महत्या दिखाने की साजिश नाकाम हुआ...

- पुलिस ने 48 घंटे में सुलझाया ब्लाइंड मर्डर, मां और भाई गिरफ्तार

रायपुर। संवाददाता

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पुलिस ने हत्या को आत्महत्या साबित करने की साजिश का पर्दाफाश करते हुए महज 48 घंटे के भीतर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया। चौकी बिरेझर पुलिस ने युवक की हत्या के आरोप में उसकी मां और भाई को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार, 29 जून 2026 को कुरूद थाना क्षेत्र के ग्राम गोजी में 23 वर्षीय नरसिंग साहू का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला था। प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा था, लेकिन पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के निर्देश पर घटनास्थल का वैज्ञानिक तरीके से निरीक्षण, साक्ष्यों का संकलन, गवाहों से पूछताछ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का गहन विश्लेषण किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि युवक की मौत गला दबाने और रस्सी से कसकर श्वास अवरुद्ध करने के कारण हुई थी तथा उसकी मृत्यु हत्यात्मक थी। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी। जांच के दौरान तकनीकी एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर मृतक के भाई नरेश साहू (22 वर्ष) और मां कमला बाई साहू (60 वर्ष) से पूछताछ की गई। पुलिस के अनुसार, दोनों ने पूछताछ में अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपियों ने बताया कि मृतक शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा था। पैसे नहीं मिलने पर विवाद बढ़ गया और गुस्से में दोनों ने पहले उसका गला दबाया, फिर नारियल की रस्सी से गला कसकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक, हत्या के बाद भी मृतक के जीवित होने की आशंका में उसे कीटनाशक दवा भी पिला दी गई।

शासकीय कार्यालयों में अब रीचार्ज' से चलेगी बिजली....

रायपुर। संवाददाता

प्रदेश के शासकीय विभागों और कार्यालयों में विद्युत खपत और बिलों के भुगतान को लेकर राज्य शासन ने एक बड़ा और युगांतरकारी निर्णय लिया है। केंद्र सरकार की आरडीएसएस योजना के दिशा-निर्देशों के तहत अब छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय कनेक्शनों में स्मार्ट मीटर के माध्यम से प्री-पेड बिलिंग अनिवार्य रूप से लागू की जा रही है। ऊर्जा विभाग द्वारा जारी समय-सारणी के अनुसार आगामी 01 अगस्त से प्रथम चरण के तहत विकासखण्ड (ब्लॉक) एवं उच्च स्तर तक के सभी शासकीय कार्यालयों में बिजली की प्री-पेड व्यवस्था शुरू हो जाएगी। इसके बाद द्वितीय चरण में इससे निचले स्तर के कार्यालयों को जोड़ा जाएगा। महानदी भवन (मंत्रालय) से जारी मार्गदर्शिका के अनुसार इस पूरी व्यवस्था को बेहद आधुनिक, पारदर्शी और व्यावहारिक बनाया गया है, जिसके तहत 30 जून 2026 की स्थिति में विभागों के कुल लंबित बकाये को फ्रीज कर दिया जाएगा और इस राशि को आगामी 4 तिमाहियों में समान किश्तों में जमा करने की छूट दी जाएगी। इस नई रीचार्ज प्रणाली को सुचारू रखने के लिए बिजली विभाग रीचार्ज खत्म होने के 7 दिन पहले से ही संबंधित विभाग के पंजीकृत नोडल अधिकारी के मोबाइल पर एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से अलर्ट भेजना शुरू कर देगा। इसके साथ ही विभाग अपनी दैनिक खपत, बची हुई शेष राशि (बैलेंस) और रीचार्ज खत्म होने की संभावित अवधि की जानकारी मोर बिजली ऐप और विभागीय वेबसाइट पर लाइव देख सकेंगे। व्यवस्था की एक बड़ी खूबी यह है कि पूरे विभाग या जिले के कनेक्शनों को एक समूह (ग्रुप आईडी) के रूप में ट्रीट किया जाएगा।

राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज लोक भवन में जैन मुनि राष्ट्र संत डॉ. मणिभद्र महाराज के नेतृत्व में संचालित सर्वोदय शांति पदयात्रा से जुड़े संतों ने सौजन्य भेंट की।

वीबी जी राम जी में 300 रु. दैनिक मजदूरी तय कर

केंद्र सरकार ने ग्रामीण श्रमिकों के साथ अन्याय किया: विनोद

रायपुर। संवाददाता

छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व संसदीय सचिव एवं महासमुंद के पूर्व विधायक विनोद सेवन लाल चंद्राकर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2026 से लागू वीबीङ्क्जीरामजी कानून के तहत ग्रामीण श्रमिकों के लिए अधिसूचित दैनिक मजदूरी दर वर्तमान महंगाई और जीवन-यापन की लागत के अनुरूप नहीं है। अधिकांश राज्यों में मजदूरी 300 रु. प्रतिदिन निर्धारित करना लाखों ग्रामीण श्रमिकों की वास्तविक जरूरतों की अनदेखी है। आज की परिस्थितियों में यह राशि एक परिवार के सम्मानजनक जीवन-यापन के लिए पर्याप्त नहीं कही जा सकती। श्री चंद्राकर ने कहा कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में श्री राहुल गांधी ने 'श्रमिक न्याय' के तहत मनरेगा सहित सभी श्रमिकों के लिए रु. 400 प्रतिदिन राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देने की घोषणा की थी। इसके विपरीत केंद्र सरकार ने 300 रु. प्रतिदिन की मजदूरी तय कर यह स्पष्ट कर दिया है कि श्रमिकों की आय बढ़ाना उसकी प्राथमिकताओं में नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा गठित डॉ. अनूप सतपथी समिति ने वर्ष 2019 में ही 375 रु. प्रतिदिन राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की सिफारिश की थी। इसके बाद महंगाई में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऐसी स्थिति में विशेषज्ञों की सिफारिशों और वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए मजदूरी दर में कहीं अधिक वृद्धि अपेक्षित थी।

धान के बाद गेहूं की खेती से बढ़ी आमदनी, जशपुर के किसान कीना राम बने मिसाल

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेकर जशपुर जिले के किसान अब खरीफ के साथ-साथ रबी फसलों की खेती कर अपनी आय बढ़ा रहे हैं। मनोरा विकासखंड के ग्राम सोगड़ा निवासी कीना राम ने धान के बाद गेहूं की खेती अपनाकर कम लागत में बेहतर उत्पादन और अतिरिक्त आमदनी हासिल की है। कीना राम ने बताया कि कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के मार्गदर्शन में उन्होंने रबी सीजन में गेहूं की खेती शुरू की। एनएफएसएनएम (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन) योजना के तहत उन्हें एक एकड़ भूमि के लिए उन्नत किस्म का गेहूं बीज अनुदान पर उपलब्ध कराया गया। उन्होंने खेत की अच्छी तैयारी कर पर्याप्त मात्रा में गोबर की खाद का उपयोग किया तथा समय-समय पर सिंचाई और खरपतवार प्रबंधन किया। इसका परिणाम यह रहा कि फसल में कीट एवं रोग का प्रकोप नहीं हुआ और गेहूं का अच्छा उत्पादन प्राप्त हुआ। कीना राम ने बताया कि वह सीमांत किसान हैं और उनके पास केवल 0.800 हेक्टेयर कृषि भूमि है।

मखाना खेती किसानों की नई आय का आधार

रायपुर। संवाददाता

प्रदेश के कृषि विकास एवं किसान कल्याण, आदिम जाति विकास, जैव प्रौद्योगिकी, मछलीपालन तथा पशुधन विकास मंत्री रामविचार नेताम ने अपने धमतरी प्रवास के दौरान बुधवार को विकासखंड कुरूद के ग्राम छाती में संचालित मखाना खेती का निरीक्षण किया। जिला प्रशासन तथा कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के समन्वित प्रयासों से विकसित इस नवाचार का अवलोकन करते हुए उन्होंने मखाना उत्पादन की पूरी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी ली तथा इसे किसानों, विशेषकर महिला स्व-सहायता समूहों की आर्थिक सशक्तता का प्रभावी माध्यम बताया। निरीक्षण के दौरान मंत्री नेताम खेत में पहुंचे और मखाना के बीज रोपण, पौधों की वृद्धि, फसल प्रबंधन, फल परिपक्व होने तथा जलाशय से फल निकालकर पारंपरिक विधि से प्रसंस्करण कर तैयार मखाना बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया को बारीकी से देखा। अधिकारियों ने बताया कि मखाना की फसल सामान्यत: 6 से 8 माह में तैयार होती है, जिसके बाद प्रसंस्करण के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाला मखाना प्राप्त किया जाता है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि ग्राम छाती में महिला शैलपुत्री एवं नई किरण महिला स्व-सहायता समूह द्वारा लगभग 29 एकड़ क्षेत्र में मखाना की सफल खेती की जा रही है। यह पहल स्थानीय महिलाओं को रोजगार एवं नियमित आय उपलब्ध कराने के साथ-साथ क्षेत्र में वैकल्पिक कृषि को भी नई दिशा दे रही है।

राजस्व मंत्री ने ग्राम झोंका को दी विकास कार्यों की सौगात

सरकार गांव,गरीब और किसानों की तरक्की के लिए प्रतिबद्ध-वर्मा

रायपुर/ संवाददाता

राज्य सरकार ग्रामीण अंचलों के चहुंमुखी विकास और बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कदम उठा रही है। इसी कड़ी में आज बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम पंचायत झोंका में विकास कार्यों की बड़ी सौगात मिली। राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने यहाँ विभिन्न जनकल्याणकारी और विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर क्षेत्र के विकास को और गति देने के लिए 27 लाख रुपये से अधिक की नई विकास योजनाओं की घोषणा भी की। ग्राम झोंका में आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने महामाया मंदिर सामुदायिक भवन, केश डबरी प्रवेश द्वार, पचरी निर्माण, महतारी सदन, मुक्तिधाम शेड, तालाब गहरीकरण तथा रंगमंच भवन सहित विभिन्न अधोसंरचना कार्यों का विधिवत भूमिपूजन किया। इसके साथ ही उन्होंने कुर्मी पारा में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण कर उसे आम जनता को समर्पित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार गांव, गरीब और किसानों की तरक्की के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना हमारी प्राथमिकता है ताकि ग्रामीणों का जीवन स्तर और बेहतर हो सके। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास में राशि की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी।ग्रामीणों की पुरजोर मांग और क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए राजस्व मंत्री ने कार्यक्रम के मंच से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं,जिसमे प्राथमिक शाला में सुलभ शौचालय निर्माण हेतु 2 लाख रुपये, छापड़ तालाब के गहरीकरण के लिए 10 लाख रुपये, मुक्तिधाम में शेड निर्माण के लिए 7 लाख रुपये, तालाबों में पचरी निर्माण के लिए 3 लाख रुपये और सामुदायिक भवन एवं ज्योति कक्ष निर्माण हेतु 5 लाख रुपये देने का ऐलान किया। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए उन्होंने जागृति महिला मंडल को 10-10 हजार रुपये की सहायता राशि देने की भी सहर्ष घोषणा की। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष, बलौदाबाजार जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा ग्राम पंचायत झोंका के सरपंच हरीराम ध्रुव सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी और क्षेत्र के गणमान्य नागरिक व ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

सरकार गांवों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध

राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने आज बलौदाबाजार- भाटापारा जिला के बलौदाबाजार विकासखंड के ग्राम पंचायत देवरी के ग्रामीणों को बड़ी सौगात देते हुए 44 लाख रुपये की लागत वाले तीन महत्वपूर्ण विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि सरकार की लोक-कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ आज गांव-गांव और घर-घर तक पहुंच रहा है, जिससे ग्रामीण अंचलों में खुशहाली और समृद्धि का एक नया दौर दिखाई दे रहा है।

जंगलों में सागौन की खुली लूट, लकड़ी माफियाओं के सामने वन विभाग बेबस, परियोजना मंडल की कार्यशैली कटघरे में

कवर्धा। कबीरधाम जिले के वन क्षेत्रों में इमारती लकड़ी की अवैध कटाई लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग मानो आंख मूंदकर बैठा हुआ है। ताजा मामला छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अंतर्गत आने वाले परियोजना मंडल कबीरधाम के रेंज तरेगांव से सामने आया है, जहां कक्ष क्रमांक 411 में बहुमूल्य सागौन के पेड़ों की लगातार कटाई किए जाने की जानकारी ने विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मगरवाड़ा नदी के आगे स्थित जंगल में वर्षों पुराने विशाल सागौन वृक्षों को लकड़ी तस्कर लगातार निशाना बना रहे हैं।

ग्रामीणों और स्थानीय सूत्रों का आरोप है कि यह अवैध कटाई कोई एक दिन की घटना नहीं, बल्कि लंबे समय से चल रहा सुनियोजित खेल है। तस्कर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में प्रवेश करते हैं। वे अपने साथ आरी और अन्य कटाई उपकरण लेकर आते हैं तथा जरूरत के अनुसार मौके पर ही पेड़ों को काटकर लकड़ी को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, ताकि उसे आसानी से बाहर निकाला जा सके। यह पूरा घटनाक्रम बताता है कि तस्करों को इलाके की पूरी जानकारी है और उन्हें कार्रवाई का कोई भय नहीं है।

सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इतने बड़े स्तर पर जंगलों में कटाई हो रही है और विभाग या तो अनजान बना हुआ है या फिर सब कुछ जानते हुए भी केवल औपचारिक कार्रवाई कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भी अवैध कटाई की सूचना मिलती है, विभाग केवल पीओआर (प्रकरण अपराध रिपोर्ट) दर्ज कर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेता है। जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई और तस्करों तक पहुंचने की इच्छाशक्ति दिखाई नहीं देती। जानकारी के अनुसार, हाल ही में दरमियानी रात लगभग 10 सागौन पेड़ों की कटाई की गई। तस्कर कटे हुए लकड़ी के हिस्सों को ले जाने की तैयारी में थे, लेकिन क्षेत्र में अचानक लोगों की आवाजाही बढ़ गई। पकड़े जाने की आशंका होते ही तस्कर कटे हुए लकड़ी के हिस्सों को छोड़कर मौके से फरार हो गए। यदि उस समय लोगों की आवाजाही नहीं होती, तो लाखों रुपये की लकड़ी आसानी से जंगल से बाहर पहुंच चुकी होती। यह घटना वन सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलने के लिए पर्याप्त है। यदि संबंधित क्षेत्र में रात्रिकालीन गश्त होती, निगरानी मजबूत होती और संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखी जाती, तो तस्करों के हौसले इतने बुलंद नहीं होते। लगातार एक ही क्षेत्र में कटाई होना सीधे-सीधे सुरक्षा तंत्र की कमजोरी को उजागर करता है।स्थानीय लोगों का कहना है कि सागौन कोई सामान्य पेड़ नहीं है। एक मजबूत इमारती सागौन वृक्ष तैयार होने में कई दशक लग जाते हैं। सरकार वन संरक्षण, वृक्षारोपण और सुरक्षा व्यवस्था पर करोड़ों रुपये खर्च करती है, लेकिन दूसरी ओर लकड़ी माफिया कुछ घंटों में लाखों की सरकारी संपत्ति साफ कर रहे हैं। इससे केवल आर्थिक नुकसान ही नहीं, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। लगातार पेड़ों की कटाई से जंगल कमजोर होंगे, जल स्रोत प्रभावित होंगे और वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास भी संकट में पड़ जाएगा। सोशल मीडिया पर मामला वायरल होने के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। लोग खुलकर विभाग और परियोजना मंडल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। चर्चाएं इस बात की भी हैं कि यदि निगरानी व्यवस्था प्रभावी होती तो जंगलों में इस तरह खुलेआम कटाई संभव ही नहीं थी। सबसे अधिक सवाल परियोजना मंडल कबीरधाम की निगरानी व्यवस्था पर उठ रहे हैं। कक्ष क्रमांक 411 जैसे संवेदनशील क्षेत्र में लगातार कटाई होना सामान्य घटना नहीं माना जा सकता। इससे साफ संकेत मिलता है कि या तो निगरानी तंत्र पूरी तरह कमजोर हो चुका है या फिर लकड़ी माफियाओं के हौसले इसलिए बुलंद हैं क्योंकि उन्हें पकड़े जाने का डर नहीं है। जनता अब जवाब चाहती है। जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होना जरूरी है। केवल फाइलों में कार्रवाई दिखाकर और छोटे कर्मचारियों पर जिम्मेदारी डालकर इस गंभीर मामले को दबाना जंगलों के साथ अन्याय होगा। कबीरधाम के जंगल केवल हरियाली नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की अमूल्य प्राकृतिक धरोहर हैं। यदि समय रहते लकड़ी माफियाओं पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई और निगरानी व्यवस्था मजबूत नहीं की गई, तो घने सागौन वन धीरे-धीरे खत्म होते जाएंगे और विभाग केवल कागजी दावों तक सीमित रह जाएगा।

कबीर के विचार सर्वसमाज का पथ प्रदर्शक : मदन साहू

डोंगरगांव नगर। ब्लॉक के ग्राम आरगांव में सदगुरु संत शिरोमणि कबीरदास के प्राकट्य दिवस श्रद्धा, आस्था व उत्साहपूर्वक मनाया गया। समारोह में कबीर संगोष्ठी आयोजित कर संत कबीर के जीवन, दर्शन व उनके समाज सुधारक विचारों पर विस्तारपूर्वक से चर्चा की गई। समारोह में सम्मिलित क्षेत्रीय जनपद सदस्य सरिता मदन साहू ने कबीरपंथी अनुयायियो की मौजूदगी में ध्वजारोहण किया।

ग्राम आरगांव में आयोजित कबीर प्राकट्य दिवस समारोह का शुभारंभ पारंपरिक विधिविधान के साथ ध्वजारोहण कर किया गया। उपरांत संगोष्ठी में वक्ताओं ने सदगुरु कबीरदास के जीवन, उनके आध्यात्मिक दर्शन तथा समाज में फैली कुरीतियों, जात-पात और भेदभाव के खिलाफ उनके संघर्ष पर विस्तार से विचार व्यक्त किए। महंत साहेब ने अपने उद्बोधन में संत कबीर दास जी के जीवन चरित्र, उनकी शिक्षाओं और समाज के प्रति उनके अमूल्य योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संत कबीर ने प्रेम, मानवता, समानता और भाईचारे का जो संदेश दिया, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। वक्ताओं ने कहा कि संत कबीर दास जी केवल एक संत या कवि नहीं थे, बल्कि वे समाज को नई दिशा देने वाले महान समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने दोहों और वचनों के माध्यम से अंधविश्वास, ऊंच-नीच, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव का विरोध करते हुए मानवता को सर्वोपरि माना।

बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 27 स्वयं सहायता समूहों को 1.08 करोड़ का बैंक ऋण वितरित

दुर्ग। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी बजरंग कुमार दुबे के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में विकासखंड पाटन द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा की रानीतराई एवं दिग्गाभाठा शाखाओं के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण उपलब्ध कराने हेतु सतत समन्वय एवं अनुश्रवण किया गया। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल से जून 2026 की अवधि में कुल 27 स्वयं सहायता समूहों को 1,08,50,000 करोड़ रुपए (एक करोड़ आठ लाख पचास हजार रुपये) का बैंक ऋण वितरित किया गया। बैंक ऋण वितरण से स्वयं सहायता समूहों के उद्यम विकास, स्वरोजगार एवं आजीविका संवर्धन को नई गति मिलेगी। इससे ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता सुदृढ़ होगी तथा वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसी क्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा की रानीतराई एवं दिग्गाभाठा शाखाओं में संध्या पखवाड़ा □ SHG Login Day" कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं, ऋण प्रक्रिया, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल बैंकिंग एवं उद्यमिता विकास की जानकारी प्रदान की गई। साथ ही पात्र समूहों के ऋण प्रकरणों का त्वरित निराकरण कर स्वीकृत ऋण का वितरण भी किया गया।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी बजरंग कुमार दुबे ने बताया कि स्वयं सहायता समूहों को समय पर बैंक ऋण उपलब्ध कराना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जिला पंचायत, विकासखंड पाटन एवं बैंक ऑफ बड़ौदा के समन्वित प्रयासों से महिलाओं को स्वरोजगार एवं उद्यम स्थापना के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन रही हैं और जिले में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिल रही है।

जनशिकायत संबंधी आवेदनों का करें त्वरित निराकरण : कलेक्टर सिंह

अधोसंरचनात्मक कार्यों की बेस लाइन सर्वे के लिए जानकारी देवें अधिकारी

दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक में विभागवार समय-सीमा के लंबित आवेदनों की गहन समीक्षा की। साथ ही लंबित आवेदनों का निराकरण समयावधि में करने के निर्देश दिये। उन्होंने मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, जन शिकायत पोर्टल के लंबित आवेदनों के निराकरण की जानकारी लेते हुए कहा कि जनशिकायत संबंधी आवेदनों का अधिकारी त्वरित निराकरण करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने जनशिकायत से संबंधित आवेदन लंबित होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को कड़ी फटकार लगायी। कलेक्टर सिंह ने सीएम हेल्पलाइन अंतर्गत विभागों को प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली। साथ ही एल-1 अधिकारी को समय-सीमा के भीतर प्रकरण निराकृत करने कहा। विभागीय अधिकारियों ने सीएम हेल्पलाइन अंतर्गत तकनीकी दिक्कतों से अवगत कराया। कलेक्टर सिंह ने ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को उच्च स्तर पर आवश्यक पहल करने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर सिंह ने ग्राम पंचायतों में राजस्व प्रकरण अविवादित, नामांतरण, बंटवारा पंजीयन की जानकारी ली। साथ ही पंचायत सचिवों द्वारा राजस्व प्रकरणों के पंजीयन उपरांत रिकार्ड दुरुस्ती पर जोर देते हुए एसएलआर को पंचायतों में पंजीकृत प्रकरणों के रिकार्ड दुरूस्ती कराने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि शासकीय प्रयोजन हेतु विभागों को भू-आबंटन के लंबित प्रकरण होने पर संबंधित विभाग राजस्व विभाग को प्रकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि भू-आबंटन की कार्यवाही में प्रगति लायी जा सके। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम एवं अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने सीएमएचओ को एनएचएम भर्ती काउंसलिंग तिथि पश्चात उसी दिन नियुक्ति आदेश जारी करने के निर्देश दिये। इसके अलावा शेष अन्य पदों पर भी भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण कराने निर्देशित किया। कलेक्टर ने कहा कि जिले में अधोसंरचनात्मक निर्माण कार्यों को गति प्रदान करने विभागीय बेस लाइन सर्वे अंतर्गत नगरीय निकायों/जनपद पंचायतों से जानकारियां मंगायी जा रही है। संबंधित विभाग के अधिकारी अधीनस्थ अधिकारियों को उक्त जानकारी मय हस्ताक्षर के साथ संबंधित निकायों/जनपद को उपलब्ध कराने निर्देशित करें। बैठक में एडीएम वीरेन्द्र सिंह, जिला पंचायत के सीईओ बजरंग दुबे, अपर कलेक्टर मती योगिता देवांगन, नगर निगम भिलाई के आयुक्त राजीव पांडे, नगर निगम दुर्ग के आयुक्त सुमीत अग्रवाल, नगर निगम रिसाली की आयुक्त मोनिका वर्मा, एसडीएम दुर्ग हरवंश सिंह मिरी, एसडीएम पाटन लवकेश ध्रुव सहित समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

जिला सहकारी विकास समिति की बैठक संपन्न

दुर्ग। देश में सहकारिता मंत्रालय के स्थापना की 05 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 29 जून से सहकारी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें प्रस्तावित गतिविधियों के अंतर्गत आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला सहकारी विकास समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सहकार से समृद्धि योजना अंतर्गत सहकारी समितियों के विस्तार हेतु रायशुमारी की गई। मत्स्य एवं दुग्ध समिति के गठन पर जोर देते हुए समितियों के विस्तार के साथ समिति सदस्यों को सक्षम बनाने हेतु विभागीय प्रयास करने के निर्देश दिये गये। बैठक में एडीएम वीरेन्द्र सिंह, जिला पंचायत के सीईओ बजरंग दुबे, उपायुक्त सहकारी संस्थाएं सतीश पाटले, उप संचालक मत्स्य मती सीमा चन्द्रवंशी, उप संचालक पशुपालन एवं दुग्ध विकास डॉ. वसीम सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

ओम शांति चौक से कालीबाड़ी हाउसिंग बोर्ड के बीच निर्माणाधीन सीसी रोड निर्माण कार्य का आयुक्त ने किया निरीक्षण

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने जोन-2 वैशाली नगर क्षेत्र का निरीक्षण कर विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन सीसी रोड और सीवर सिस्टम पाइपलाइन एवं बैक लाइन की कच्ची नालियों की सफाई व्यवस्था अवलोकन करते हुए अधिकारियों को कार्य जल्द पूर्ण कराने निर्देशित किये है। निगम आयुक्त ने ओम शांति चौक से कालीबाड़ी हाउसिंग बोर्ड के बीच निर्माणाधीन सीसी रोड का निरीक्षण किया और नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना क्षेत्र में सीवर सिस्टम पाइपलाइन एवं बैक लाइन की कच्ची नालियों की सफाई व्यवस्था का भी अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बारिश के मौसम को देखते हुए नालियों की समय पर सफाई सुनिश्चित की जाए, ताकि जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो और आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। आयुक्त ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को विकास कार्यों की नियमित निगरानी करने, निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने तथा सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना निगम की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान कार्यपालन अभियंता अरविंद शर्मा, सहायक अभियंता श्वेता वर्मा, उप अभियंता अशोक देवांगन, जोन स्वास्थ्य अधिकारी शंकर सहानी, स्वच्छता निरीक्षक अंजनी सिंह, जोनल एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

मोहड में निषाद समाज सामाजिक भवन का महापौर मधुसूदन ने किया लोकार्पण

मेयर बोले- भवन बनने से नहीं एकजूट होकर लोगों के हित में कार्य करने से विकास होगा

राजनांदगांव। नगर निगम द्वारा वार्ड नं. 49 के मोहड में विधायक निधि अंतर्गत 10 लाख रुपए की लागत से निषाद समाज सामाजिक भवन का निर्माण किया गया है। महापौर मधुसूदन यादव ने सामाजिक बुधओं की उपस्थिति में फीता काटकर पट्टीका का अनावरण कर लोकार्पण किया। कार्यक्रम में वार्ड पार्षद संजय रजक सहित निषाद समाज के अध्यक्ष गणेश सातर, उपाध्यक्ष भुवन निषाद, सचिव दिलहरण निषाद, कोषाध्यक्ष हेमनाथ निषाद विशेष रूप से उपस्थित थे। लोकार्पण कार्यक्रम में अपने संबोधन में महापौर यादव ने कहा कि सामाजिक बंधुओं की मांग पर विधायक निधि से सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है। भवन निर्माण होने से अब समाज के लोगों को सामाजिक, धार्मिक एवं अन्य आयोजनों के लिये एक उचित स्थान मिल गया। उन्होंने कहा कि हमारे विधायक डॉ. रमन सिंह एवं सांसद संतोष पाण्डे शहर विकास में अपनी निधि सहृदयता से देते हैं, समाज की प्रगति के लिए उनके द्वारा हर संभव मदद किया जाता है। उन्होंने कहा कि भवन बनने से समाज का विकास नहीं होता वरन एकजूट होकर समाज के लोगों के हित में कार्य करने से, समाज के बच्चों को शिक्षित करने से समाज का विकास होता है। भवन में पानी की सुविधा के लिए जल्द टंकी लगाया जायेगा, इसके अलावा समाज को आवश्यकता अनुसार इसी प्रकार का सहयोग समय समय पर किया जायेगा। कार्यक्रम के पूर्व में समाज के पदाधिकारियो ने महापौर का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। तत्पश्चात पूजा अर्चनाकर सामुदायिक भवन का महापौर ने विधिवत लोकार्पण किया। इस अवसर पर निषाद समाज के लोग उपस्थित थे।

सभी स्कूलों में बच्चों के आधार सत्यापन का कार्य प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराने कहा

कलेक्टर ने दिए निर्देश..सीएम हेल्पलाइन में मिले आवेदनों का समय पर करें निराकरण

राजनांदगांव। कलेक्टोरेट में साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों एवं शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। इसमें कलेक्टर जितेंद्र यादव ने सीएम हेल्पलाइन 1076 में प्राप्त आवेदनों, जन शिकायतों, शासकीय योजनाओं तथा सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों तथा लंबित प्रकरणों के समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन 1076 में विभागवार प्राप्त आवेदनों के निराकरण के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण करना अनिवार्य है। इसके लिए सभी विभाग जिम्मेदारी के साथ निराकरण करें। इसके लिए लगातार ऑनलाईन मॉनिटरिंग करने कहा। कलेक्टर ने विधानसभा सत्र से संबंधित के प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को जिले में वृहद स्तर पर पौधरोपण की तैयारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों के आधार सत्यापन का कार्य प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने साप्ताहिक समय-सीमा, पीजीएन, पीजी पोर्टल एवं जनदर्शन के लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा की। कलेक्टर ने खरीफ सीजन में खाद-बीज वितरण एवं भण्डारण और खेती-किसानी के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने किसानों को धान के बदले दलहन, तिलहन एवं अन्य फसल लेने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने कहा। जिससे किसानों को कम लागत में अधिक आमदनी मिल सके। उन्होंने सभी ग्रामों में कृषि चौपाल का आयोजन कर अधिक से अधिक किसानों को शासन की योजनाओं की जानकारी देने के निर्देश दिए।

हाई रिस्क गर्भवतियों की स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से करें

कलेक्टर ने कहा कि हाई रिस्क वाली गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग का कार्य अनिवार्य रूप से किया जाए और इस कार्य को तेज गति से करने के निर्देश दिए। उनकी सोनोग्राफी, स्वास्थ्य सुविधाओं, दवाईयों पर विशेष ध्यान देते हुए कार्य करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही हाई रिस्क वाली गर्भवती महिलाओं से प्रतिदिन उनके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी मोबाईल के माध्यम से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने एचपीवी वैक्सीनेशन के संबंध में जानकारी ली। जिले में 3 हजार 800 किशोरी बालिकाओं को एचपीवी वैक्सीन लगाया जा चुका है। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को स्कूलों का रोस्टर बनाकर एचपीवी वैक्सीनेशन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। एक माह में लक्ष्य के अनुरूप शत प्रतिशत करने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के लिए जागरूकता बढ़ाने के निर्देश

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए व्यापक जनजागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह योजना आम नागरिकों के बिजली व्यय को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। जिले में अब तक 3 हजार 620 हितग्राहियों द्वारा सोलर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं। जिससे हितग्राही स्वयं ऊर्जादाता बन चुके हैं। नागरिकों को इस योजना से लाभान्वित करने के लिए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

जिले में पीएम आवास प्लस 2.0 की चयन प्रक्रिया जारी, 80 हजार से अधिक हितग्राही प्रारंभिक सूची में पात्र

दुर्ग। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत दुर्ग जिले में आवास प्लस 2.0 सर्वे सूची के माध्यम से वास्तविक परिवारों को लाभांवित करने की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ जारी है। योजना के तहत ऐसे परिवारों को जोड़ा गया है, जिनके नाम सामाजिक-आर्थिक जनगणना 2011 या आवास प्लस 2018 की सूची में शामिल नहीं थे। जिले में कुल 95,783 हितग्राहियों का सर्वे किया गया था, जिसमें से 81,600 का सर्वेयरों द्वारा और 14,183 का हितग्राहियों द्वारा स्वयं (सेल्फ सर्वे) कर भौतिक सत्यापन कराया गया। भारत सरकार के आवास सॉफ्ट पोर्टल द्वारा ऑनलाइन मूल्यांकन के बाद प्रारंभिक रूप से 80,835 हितग्राही पात्र और 14,948 हितग्राही अपात्र श्रेणी में दर्ज हुए हैं। इस सूची को पारदर्शी बनाने और त्रुटियों को सुधारने के लिए विगत 24 जून 2026 को सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया, जहां सूची का सार्वजनिक वाचन कर प्राथमिकता तय की गई। स्थानीय स्तर पर संवेदनशीलता का उदाहरण देते हुए ग्राम पंचायत डूमरडीह में 32 अपात्र प्रकरणों पर चर्चा कर प्रस्ताव पारित किया गया। इसी तरह ग्राम पंचायत सेलूद में तकनीकी कारणों से सूची में नहीं दिख रहे 252 छूटे हुए हितग्राहियों को ग्राम सभा ने विचार-विमर्श के बाद वास्तविक रूप से पात्र मानते हुए विशेष प्रस्ताव जनपद कार्यालय को भेजा है। जिला पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बजरंग दुबे ने बताया कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन डेटाबेस पर आधारित है, इसलिए प्रशासनिक स्तर पर किसी भी मनमाने फेरबदल की गुंजाइश नहीं है।

मुख्यमंत्री से मिली सर्वधर्म सेवा संस्था की टीम

अंगदान करने वालों को राजकीय सम्मान देने की मांग

छत्तीसगढ़ को अंगदान और देहदान के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए सौंपा 16 सूत्रीय सुझाव-पत्र

भिलाई। छत्तीसगढ़ को अंगदान एवं देहदान के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में सर्वधर्म सेवा संस्था, भिलाई ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य भेंट की। संस्था के संरक्षक इंद्रजीत सिंह 'छोटू भईया' के सहयोग एवं मार्गदर्शन में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को 16 बिंदुओं का विस्तृत सुझाव-पत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि पूरे प्रदेश में अंगदान और देहदान को जन-जागरूकता अभियान के रूप में संचालित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पुनीत कार्य से जुड़ सकें। संस्था ने यह भी मांग रखी कि अंगदान करने वाले दाताओं को मरणोपरांत राजकीय सम्मान प्रदान किया जाए, जिससे समाज में अंगदान के प्रति सम्मान, विश्वास और प्रेरणा का वातावरण निर्मित हो सके।संस्था के प्रतिनिधियों ने बताया कि प्रदेश में अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता वाले हजारों मरीज समय पर अंग नहीं मिलने के कारण कठिनाइयों का सामना करते हैं। यदि व्यापक जनजागरूकता और प्रभावी नीतिगत पहल की जाए, तो अनेक लोगों को नया जीवन मिल सकता है।

समाज के लिए जीवनदान का सबसे बड़ा माध्यम है अंगदान : **इंद्रजीत सिंह 'छोटू भईया'**-सर्वधर्म सेवा संस्था के संरक्षक इंद्रजीत सिंह 'छोटू भईया' ने कहा कि अंगदान केवल एक दान नहीं, बल्कि किसी जरूरतमंद को नया जीवन देने का सबसे बड़ा मानवतावादी कार्य है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता इस बात की है कि समाज में अंगदान और देहदान को लेकर मौजूद भ्रांतियों को दूर किया जाए तथा इसे जन-आंदोलन का स्वरूप दिया जाए। उन्होंने कहा, यदि शासन, चिकित्सा संस्थान, सामाजिक संगठन और जागरूक नागरिक एक साथ मिलकर कार्य करें तो छत्तीसगढ़ अंगदान के क्षेत्र में पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकता है। अंगदान करने वाले परिवारों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि उनके निर्णय से कई लोगों को नया जीवन मिलता है। ऐसे दाताओं को मरणोपरांत राजकीय सम्मान दिया जाना समाज के लिए एक सकारात्मक और प्रेरणादायक संदेश होगा।

भूमिपूजन से वार्ड 36 को मिली विकास कार्यों की सौगात, 17.50 लाख से बनेंगी नालियां और पुलिया

महापौर अलका बाघमार ने कहा शहर के प्रत्येक वार्ड में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता

जलभराव की समस्या से मिलेगी राहत, नागरिकों ने विकास कार्यों का किया स्वागत

दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा शहर में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और नागरिकों की वर्षों पुरानी समस्याओं के निराकरण की दिशा में लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में वार्ड क्रमांक 36 गंजपारा (पुलिस लाइन क्षेत्र) में लगभग 17.50 लाख की लागत से विभिन्न स्थानों पर नाली एवं पुलिया निर्माण कार्यों का विधिवत भूमिपूजन महापौर अलका बाघमार ने लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर,एमआईसी शिव नायक वार्ड पार्षद प्रतिभा सुरेश गुप्ता तथा बड़ी संख्या में उपस्थित वार्डवासियों की मौजूदगी में किया। इस स्वीकृत कार्य के अंतर्गत बांधा तालाब निचली बस्ती एवं जीवन प्लाजा के पीछे, मंदिर से चौहान निवास तक, मोहन बाल मंदिर के आसपास तथा सरदार पटेल स्कूल के सामने नाली एवं पुलिया का निर्माण कराया जाएगा। इन कार्यों के पूर्ण होने से क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था मजबूत होगी, बरसात के दौरान होने वाले जलभराव से राहत मिलेगी तथा नागरिकों को आवागमन में बेहतर सुविधा प्राप्त होगी। भूमिपूजन के दौरान महापौर अलका बाघमार ने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य प्रत्येक वार्ड में समान रूप से विकास कार्य कर नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि सड़क, नाली, पुलिया, पेयजल एवं स्वच्छता जैसी आवश्यक सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए लगातार कार्य किए जा रहे हैं, ताकि शहर का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना नगर निगम की जिम्मेदारी है और इसी भावना के साथ विकास कार्यों को गति दी जा रही है। महापौर ने कहा कि बरसात के मौसम में जल निकासी की समुचित व्यवस्था अत्यंत आवश्यक होती है। इसलिए जिन क्षेत्रों में नालियों और पुलियों की आवश्यकता महसूस की गई, वहां प्राथमिकता के आधार पर कार्य स्वीकृत कराए गए हैं। इन निर्माण कार्यों के पूरा होने से क्षेत्रवासियों को लंबे समय तक इसका लाभ मिलेगा और स्वच्छ एवं व्यवस्थित वातावरण तैयार होगा।

इस अवसर पर वार्ड पार्षद प्रतिभा सुरेश गुप्ता एवं स्थानीय नागरिकों ने वार्ड में विकास कार्यों की स्वीकृति के लिए महापौर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन निर्माण कार्यों से क्षेत्र की वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान होगा और आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। कार्यक्रम में उपअभियंता मोहित मरकाम, अजय शर्मा, कमल नारायण रूंगटा, विजय गुप्ता, मनोज श्रीवास्तव, सुरेश गुप्ता, प्रहलाद, महेंद्र सक्सेरिया, सरिता शर्मा, किरण सेन, चंचल शर्मा सहित बड़ी संख्या में वार्डवासी उपस्थित रहे।

राजस्व प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में करने के दिए निर्देश

कलेक्टर ने की राजस्व प्रकरणों की समीक्षा

दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में लंबित राजस्व प्रकरणों के त्वरित एवं समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, खाता विभाजन, भू-अभिलेख, भू-अर्जन, डायवर्सन और नक्शा बटांकन से जुड़े मामलों में समय-सीमा से बाहर लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में तहसीलवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अविवादित नामांतरण एवं बंटवारे के मामलों का अनिवार्य रूप से निराकरण किया जाए, ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। कलेक्टर ने निकायवार पट्टाधारी सर्वे की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को 15 जुलाई तक सर्वे कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही अतिक्रमण के प्रकरणों का परीक्षण कर तत्काल कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने एग्रीस्टैक पोर्टल पर किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने तथा बकेट क्लेम में लंबित किसानों के पंजीयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में एग्रीस्टैक बकेट क्लेम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को बकेट क्लेम की विस्तृत मार्गदर्शिका तैयार कर ऑपरेटरों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को योजना का लाभ समय पर मिल सके। कलेक्टर ने समय-सीमा से बाहर लंबित अविवादित नामांतरण एवं खाता विभाजन के सभी प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। वहीं विवादित नामांतरण एवं खाता विभाजन के मामलों में पटवारियों द्वारा प्रतिवेदन अथवा फर्द प्रस्तुत नहीं किए जाने पर संबंधित पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। सीमांकन प्रकरणों की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि समय-सीमा से बाहर लंबित सभी मामलों का अभियान चलाकर जल्द निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि सीमांकन पूरा होने के बाद संबंधित पटवारी तीन दिवस के भीतर अपनी रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।

बैठक में कोटवार भूमि के विक्रय से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई। भू-आबंटन के प्रकरणों की प्रगति की जानकारी ली। सहकारी समितियों के लिए भू-आबंटन हेतु उपयुक्त भूमि का चयन करने के निर्देश दिए। स्वामित्व योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने तहसीलवार प्रगति की जानकारी ली तथा योजना के तहत तैयार नए पट्टों का वितरण जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराने के निर्देश दिए। उन्होंने भारतमाला परियोजना एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत भू-अर्जन और मुआवजा भुगतान की प्रगति की भी समीक्षा की। अभिलेख शुद्धता अभियान के तहत संयुक्त खातेदारों के नाम अलग-अलग दर्ज करने, खसरा विहीन नक्शों का सुधार तथा अभिलेख दुरुस्ती का कार्य एक सप्ताह के भीतर पूरा करने के निर्देश देते हुए कलेक्टर ने कहा कि निर्धारित समय में कार्य पूरा नहीं करने वाले संबंधित पटवारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने को कहा। बैठक में अपर कलेक्टर वीरेन्द्र सिंह, अपर कलेक्टर मती योगिता देवांगन सहित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

नगर पालिका में पांच एल्डरमैन नियुक्त, विकास कार्यों को मिलेगी नई गति, अब 24 जनप्रतिनिधी सुनेंगे जनता की समस्या

अमलेश्वर। दुर्ग जिले के अंतर्गत नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगमों में एल्डरमैन की नियुक्ति कर दी गई है। इसी क्रम में नगर पालिका परिषद अमलेश्वर में पांच भाजपा कार्यकर्ताओं को एल्डरमैन नियुक्त किया गया है। इनमें सुनील शर्मा, भारती यादव, लक्ष्मी देवांगन, हीरालाल साहू एवं रामाधार साहू के नाम पर मुहर लगी है। एल्डरमैन की नियुक्ति के बाद नगर पालिका परिषद अमलेश्वर की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। नगरवासियों को उम्मीद है कि अब जनहित के मुद्दों और विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। लंबे समय से नगर के लोग मूलभूत सुविधाओं की कमी और अवैध कब्जों जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में नव-नियुक्त एल्डरमैनों से इन समस्याओं के समाधान की अपेक्षा की जा रही है। नगर में अब इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि पांचों एल्डरमैन नगर के विकास में किस प्रकार अपनी भूमिका निभाएंगे और आम नागरिकों की समस्याओं को कितनी जिम्मेदारी के साथ पालिका प्रशासन के समक्ष रखकर उनके समाधान के लिए प्रयास करेंगे। लगातार जनहित के मुद्दों पर अपेक्षित कार्य नहीं होने के कारण विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष के पार्षदों में भी नाराजगी देखी जा रही थी। ऐसे में एल्डरमैनों की नियुक्ति से नगरवासियों को उम्मीद है कि विकास कार्यों में आ रही रुकावटों पर विराम लगेगा। अब नगर पालिका परिषद अमलेश्वर में 18 पार्षदों और 5 एल्डरमैन , अध्यक्ष सहित कुल 24 जनप्रतिनिधि पालिका प्रशासन के साथ मिलकर नगर के विकास और जनसमस्याओं के समाधान के लिए कार्य करेंगे।

एनएसपीसीएल ने सीएसआर के तहत नगर निगम को दिए दो आधुनिक मोबाइल टॉयलेट

- भिलाई-चरौदा को मिली स्वच्छता की नई सौगात,सार्वजनिक आयोजनों में बढ़ेगी नागरिक सुविधा

भिलाई-चरौदा। शहर में स्वच्छता और जनसुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए एनएसपीसीएल भिलाई ने अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम के तहत भिलाई-चरौदा नगर निगम को दो अत्याधुनिक मोबाइल टॉयलेट प्रदान किए हैं। इन मोबाइल टॉयलेटों का उपयोग धार्मिक आयोजनों, मेलों, सामाजिक कार्यक्रमों एवं अन्य बड़े सार्वजनिक आयोजनों में नागरिकों को स्वच्छ और सुविधाजनक शौचालय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। मोबाइल टॉयलेट हस्तांतरण कार्यक्रम में नगर निगम के जनप्रतिनिधियों एवं एनएसपीसीएल के अधिकारियों की उपस्थिति में इन सुविधाओं को नगर निगम को सौंपा गया। इस पहल को शहर की स्वच्छता व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, शहर में आयोजित होने वाले बड़े आयोजनों के दौरान अस्थायी शौचालय व्यवस्था एक बड़ी चुनौती होती है। आधुनिक मोबाइल टॉयलेट उपलब्ध होने से अब नागरिकों, विशेषकर महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों एवं बाहर से आने वाले लोगों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। इससे आयोजनों में स्वच्छता बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। महापौर निर्मल कोसरे ने एनएसपीसीएल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नगर निगम नागरिकों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि मोबाइल टॉयलेटों के शामिल होने से निगम की जनसेवा क्षमता और अधिक मजबूत होगी तथा सार्वजनिक कार्यक्रमों में स्वच्छता और नागरिक सुविधा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि उद्योग और स्थानीय निकायों के बीच इस प्रकार का सहयोग शहर के विकास और जनहित के कार्यों को नई गति प्रदान करता है। कार्यक्रम में एनएसपीसीएल के प्रतिनिधि सरफराज उपस्थित रहे। इस अवसर पर एमआईसी सदस्य मोहन साहू एवं वेंकट रमना, पार्षद डे साहब वर्मा, टेनेन्द्र ठाकरे, डी. वेंकट राव सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। नगर निगम ने एनएसपीसीएल के इस सहयोग को जनहित और स्वच्छता के क्षेत्र में एक सराहनीय पहल बताते हुए भविष्य में भी ऐसे सहयोगात्मक प्रयासों की अपेक्षा जताई है।

निगम प्रशासन का मानना है कि इससे स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों को भी मजबूती मिलेगी और शहर में नागरिक सुविधाओं का विस्तार होगा।

संसाधन स्त्रोत केंद्र हेतु स्पीच थैरेपिस्ट और अटेंडेंट पदों के लिए आवेदन आमंत्रित

दुर्ग। जिले में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण शासकीय पहल की गई है। राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़, रायपुर के दिशा-निर्देशों के परिपालन में, जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा दुर्ग द्वारा विकासखण्ड स्तर पर संचालित संसाधन स्रोत केन्द्रों के लिए अस्थाई नियुक्तियों हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से संसाधन स्रोत केन्द्रों में रिक्त पदों को भरा जाएगा ताकि विशेष बच्चों को आवश्यक थेरेपी और सहायता सुलभ कराई जा सके। जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस भर्ती अभियान के तहत 'स्पीच थैरेपिस्ट' के 01 पद पर अस्थाई रूप से नियुक्ति की जाएगी, जिसके लिए निश्चित मानदेय 20,833 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, केंद्र के सुचारू संचालन और बच्चों की देखभाल हेतु 'अटेंडेंट' के 02 अस्थाई पदों पर भी भर्ती की जा रही है, जिसके लिए 7,000 रुपये प्रति माह का निश्चित मानदेय देय होगा। इच्छुक और योग्य आवेदक इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 निश्चित की गई है। आवेदकों की सुविधा के लिए विभाग द्वारा डिजिटल लिंक जारी किए गए हैं। योग्य उम्मीदवार स्पीच थैरेपिस्ट पद के लिए निर्धारित गूगल लिंक और अटेंडेंट पद के लिए पर जाकर अपना आवेदन सफलता पूर्वक दर्ज कर सकते हैं। इस भर्ती से संबंधित विस्तृत शैक्षणिक योग्यता, नियम एवं अन्य शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए आवेदक किसी भी कार्य दिवस में जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा दुर्ग के सूचना पटल का अवलोकन कर सकते हैं। यह आदेश जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना अधिकारी अरविंद कुमार मिश्रा द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों से कलेक्टर सिंह ने किया संवाद, पढ़ाई और भविष्य पर की चर्चा

दुर्ग। कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता-पिता को खो चुके दस बच्चों (प्रीति टंडन, करीना टंडन, स्पनिल बोस, दुष्यंत कुमार साहू, जयंत कुमार साहू, वैभव बंजारे, सुल्ताना खान, यमुना ठाकुर, जय ठाकुर, रविन्द्र कुमार टंडन) से कलेक्टर अभिजीत सिंह ने आज आत्मीय मुलाकात कर संवाद किया। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में उन्होंने बच्चों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत करते हुए उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य की योजनाओं की जानकारी ली। कलेक्टर सिंह ने बच्चों से उनके वर्तमान विद्यालय, पढ़ाई की स्थिति और रुचियों के बारे में विस्तार से पूछा। उन्होंने यह भी जाना कि बच्चे भविष्य में क्या बनना चाहते हैं और किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। उन्होंने छात्रवृत्ति की उपलब्धता और शासन द्वारा दी जा रही अन्य सहायता योजनाओं के बारे में भी बच्चों से सीधे जानकारी ली। भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पीएम केयर्स में लाभान्वित बालक/बालिकाओं को स्पांसरशिप योजना, महतारी दुलार योजना, एक्सग्रेसिया (आपदा प्रबंधन राहत कोष), 23 वर्ष पूर्ण होने पर एकमुश्त 10 लाख रूपए की राशि, कक्षा पहली से 12वीं तक अध्ययनरत लाभार्थियों को प्रति वर्ष 20 हजार रूपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास अधिकारी को सभी बच्चों के आधार कार्ड, बायोमेट्रिक अपडेट, 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवाओं के वोटर आईडी कार्ड एवं जाति प्रमाण पत्र बनाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी बच्चों से उनकी वर्तमान पढ़ाई और शैक्षणिक प्रगति की जानकारी ली। बच्चों ने अपने-अपने अध्ययन और भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया। इस दौरान कलेक्टर ने उन्हें मन लगाकर पढ़ाई करने, लक्ष्य निर्धारित करने तथा उज्ज्वल भविष्य के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया। इस दौरान महिला एवं बाल विकास के अधिकारी अजय साहू, जिला बाल संरक्षण अधिकारी प्रीति डांगरे, परियोजना समन्वयक चंद्रप्रकाश पटेल, जिला बाल संरक्षण ईकाई के कर्मचारी उपस्थित थे।

शौर्य चक्र से सम्मानित जवान भोजराम साहू को कलेक्टर ने किया सम्मानित

दल्लीराजहरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से शौर्य चक्र से सम्मानित होने वाले जिले के वीर जवान भोजराम साहू का कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने संयुक्त जिला कार्यालय में स्थित अपने कक्ष में शॉल एवं पौधा भेंट कर सम्मान किया। इस अवसर पर कलेक्टर मिश्रा ने जिले के डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम ढोरींठेमा निवासी असम रायफल्स के जवान भोजराम साहू की अदम्य वीरता एवं कर्तव्य परायणता की भूरी-भूरी सराहना की। मिश्रा ने कहा कि साहू की गौरवपूर्ण उपलब्धि से बालोद जिला गौरवान्वित हुआ है। कलेक्टर ने भोजराम साहू की देश प्रेम एवं अदम्य वीरता को सभी के लिए प्रेरणादायी बताते हुए उनके यशस्वी एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर मिश्रा ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए साहू एवं उनके परिजनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। उल्लेखनीय है कि असम राइफल्स के जवान भोजराम साहू को यह सम्मान वर्ष 2025 में मणिपुर के टेंगनौपाल क्षेत्र में आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में दिखाए गए अदम्य साहस के लिए मिला है। अभियान के दौरान आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर घात लगाकर अचानक हमला कर दिया था। ऐसी अत्यधिक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच भोजराम ने अपनी जान की परवाह न करते हुए आगे बढ़कर मोर्चा संभाला। उन्होंने बेहद नजदीक से आतंकियों पर जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान उन्हें एक गोली भी लगी, लेकिन घायल होने के बावजूद वे पीछे नहीं हटे और अपनी जिम्मेदारी पर डटे रहे। उनके इस अदम्य साहस ने अभियान को सफल बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई थी।

ग्रामीण परिवारों को अब 125 दिनों का गारंटीशुदा रोजगार, मजदूरी दर बढ़कर 300 रुपये प्रतिदिन

जिले में विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन का शुभारंभ

दुर्ग। जिला पंचायत सभा कक्ष, दुर्ग में विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (जी-रामजी) के शुभारंभ के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ तिरुपति (आंध्र प्रदेश) से केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वर्चुअल माध्यम से किए गए राष्ट्रीय शुभारंभ के साथ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विजय बघेल तथा विधायक ललित चंद्राकर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष मती सरस्वती बंजारे ने की। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दुर्ग बजरंग कुमार दुबे, जिला पंचायत उपाध्यक्ष पवन शर्मा, जनपद पंचायत दुर्ग की अध्यक्ष मती कुलेश्वरी देवांगन, जिला पंचायत सदस्य सु प्रिया साहू, मती श्रद्धा साहू, मती नीलम चंद्राकर सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। सांसद विजय बघेल ने कहा कि विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन, विकसित भारत-2047 के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रत्येक पंजीकृत ग्रामीण परिवार को अब 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों का कानूनी रूप से गारंटीशुदा मांग आधारित रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही छत्तीसगढ़ में मजदूरी दर 262 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है, जिससे ग्रामीण श्रमिकों की आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत रोजगार की मांग प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर कार्य उपलब्ध कराने तथा मजदूरी का भुगतान सात दिनों के भीतर सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। समय पर रोजगार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में पात्र हितग्राहियों को नियमानुसार गारंटीकृत बेरोजगारी भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक व्यय की सीमा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दी गई है। योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास के चार प्रमुख क्षेत्रों जल सुरक्षा, मूलभूत ग्रामीण अधोसंरचना, आजीविका संवर्धन एवं आपदा-निवारण पर विशेष फोकस किया जाएगा। ग्राम पंचायतों में स्थायी परिसंपत्तियों एवं आधारभूत अधोसंरचना के निर्माण से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा ग्राम पंचायतों के सतत एवं समग्र विकास को गति मिलेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दुर्ग बजरंग कुमार दुबे ने बताया कि योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के माध्यम से विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार की जाएगी। प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल के अनुरूप आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर विकास कार्यों का चयन किया जाएगा।

स्वत्वाधिकारी , प्रकाशक, एवं मुद्रक ज्वाला प्रसाद अग्रवाल द्वारा असमा पब्लिशर्स प्रा. लि. जयस्तंभ चौक, रायपुर, पिन - 492001 छत्तीसगढ़ से मुद्रित एवं झुलेलाल मंदिर के पीछे, पाटनकर कालोनी, सिंधी कालोनी, दुर्ग पिन- 491001 (छ.ग.) से प्रकाशित।
संपादक - ज्वाला प्रसाद अग्रवाल । e mail - jwalaexpress@gmail.com , मोबाईल- 9993590905, 7000489995